

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> अन्नदाता किसानों की समृद्धि...



संकीर्ण स्वार्थों की राजनीति कर रहा विपक्ष : नड्डा विधायक डोमनलाल का निधन

लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ सभा में गरजे केंद्रीय मंत्री

दुर्ग। दुर्ग में आयोजित भाजपा के लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए. दिल्ली में एक नवम्बर को आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आयोजित सभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब इलेक्शन जीत जाए तो वह होशियार और हार जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब कहते हैं. आज हमें इसी अराजकता से बचने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री विनय जायसवाल, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चन्द्राकर, रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय की मौजूदगी में महेश कालोनी ने आयोजित सभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को खूब खरी-खोटी सुनाई.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बस्तर में एक जगह है चांदा मेटा, जहां पहली बार चुनाव हुआ. इस देश में पहली बार एसएआर नहीं हुआ है. 10 बार इन्होंने कराया, हमने सिर्फ दो बार एसआईआर कराया. एक बार अटल जी के समय और दूसरी बार अब. 2 करोड़ 13 लाख ऐसे लोगों के नाम कटे हैं, जो अपसेंट थे, जो इस देश



के नागरिक नहीं हैं. एमएलसी चुनावों में इनको पता चल गया कि ईवीएम या बैलेट से नहीं जनता के विश्वास से चुनाव जीता जाता है. हम हिमांचल और कर्णाटक में भी अब हम चुनाव जीतेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भारत की जनता की बदौलत चुनाव में नहीं आना चाहते, ये घुसपैठियों के बदौलत चुनाव जीतना चाहते हैं. बॉर्डर के 9 जिलों में वोट प्रतिशत बढ़ा है. इस दौरान इंडिया गठबन्धन के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में जो 35 साल से चुनाव नहीं जीत पाए और सरकार नहीं बना पाए, वो चोरी की बात करते हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ मार्च के दौरान बोलते हुए, नड्डा ने स्थापित संवैधानिक सुरक्षा-व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की निंदा की।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह बड़े गर्व की बात है कि भारत का

निर्वाचन आयोग जिस तरह से चुनाव कराता है, उसके लिए उसे दुनिया भर में सराहा जाता है और उसकी बहुत तारीफ होती है। इसके बावजूद, कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को डरा-धमकाकर गलत कोशिशें कर रहे हैं। नड्डा ने गांधी के राजनीतिक कदमों की तुलना एक ऐसे छात्र से की, जो अपनी खराब पढ़ाई के लिए शिक्षकों को दोष देता है। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे स्कूल के दिनों के एक खास तरह के बच्चे की याद दिलाते हैं- जब ऐसा बच्चा परीक्षा पास कर लेता है, तो वह खुद को बहुत होशियार बताता है, लेकिन जब

लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने आपातकाल लगाया : सीएम साय

सभा में मौजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज हम सब उनके खिलाफ एकत्रित हुए हैं, जो देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं. लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने आपातकाल लगाकर सबको जेल में डाल दिया, मीडिया में सेंसरशिप लगाया, धारा 356 का गलत उपयोग किया. ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले जब चुनाव जीत जाते हैं, तब कोई विरोध नहीं करते, पर जब चुनाव हार जाते हैं, तब चुनाव में गड़बड़ी की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र वाले ये लोग ही आज देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं. इनके इरादों को जनता समझती है. और ये कभी

वह फेल हो जाता है - जो कि अक्सर होता है - तो वह शिक्षक को दोष देता है। उन्होंने चुनाव नतीजों पर गांधी की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, अगर वे चुनाव जीत जाते हैं, तो खुद को जीनियस मानते हैं; लेकिन जब वे बार-बार हारते हैं, तो चुनाव आयोग को दोष देते हैं।



पीएम मोदी से रूबरू हुई छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमी हीना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं आज अपनी मेहनत, उद्यमशीलता और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। इसकी एक प्रेरणादायक झलक गुजरात के एकता नगर में आयोजित भारत पर्व 2026 में देखने को मिली, जब कोरिया जिले की महिला उद्यमी एवं मिलेट्स कैफे की संचालिका श्रीमती हीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने का अवसर मिला।

विपक्षी की रैली, जवाब में भाजपा का देशत्यापी अभियान

नवंबर) को सुबह 11 बजे दिल्ली के हरि नगर इलाके में निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई प्रमुख नेताओं के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ सिख नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है।

इस प्रस्तावित मार्च की एक मुख्य विशेषता 1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी होगी। माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी से 1984 की हिंसा का मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की



रैली के जवाब में अपनी रणनीति तैयार कर रही है।

इस बीच, 1 नवंबर की रैली की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक हुई। विपक्षी गठबंधनचलो

दिल्ली रामलीला मार्च के बैनर तले इस प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है। उम्मीद है कि नेता मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। इस रैली में देश के विभिन्न हिस्सों से राजनीतिक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। दक्षिणी राज्यों सहित कई विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। कई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भी इसमें शामिल होने

की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की उस रैली की आलोचना की है, जो त्योहारों के दौरान खरीददारी के समय आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों और आम लोगों को परेशानी हो सकती है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, पासवान ने एएनआई को बताया कि आप अपनी रैली जरूर कर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

प्रमुख समाचार

सौरव दास की नागरिकता पर मद्रास हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

चेन्नई । मद्रास हाईकोर्ट ने पत्रकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास की पहचान और राष्ट्रीयता की जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, सौरव दास और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दास की नागरिकता और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच कराने के साथ ही उनके सोशल मीडिया खातों को बंद करने की मांग भी की गई है। मामला अब अदालत में विचाराधीन है। मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने सौरव दास, केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उनका जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी अब संबंधित पक्षों को याचिका में लगाए गए आरोपों और मांगों पर अपना पक्ष रखना होगा।

वोट चोरी के आरोपों पर संसद में बहस करने का खुला चैलेंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस चर्चा के लिए सहमत नहीं होंगे। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शाह ने कहा कि मैं वोट चोरी (वोट चोरी के आरोपों) पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हूँ। लेकिन राहुल बाबा कभी सहमत नहीं होंगे। वे संसद में इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों पर हंगामा खड़ा करेंगे। शाह ने कहा कि मैं राहुल और अखिलेश को चुनौती देता हूँ कि वे संसद के भीतर हर आरोप पर चर्चा करें। चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते; वे सड़कों पर ड्रामा करना चाहते हैं। गृह मंत्री का यह तीखा हमला विपक्ष की उन योजनाओं के ठीक पहले आया है।

अखिलेश का पलटवार, हार जीत भाषणों से तय नहीं होती

लखनऊ। अमित शाह के बयान पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। राजधानी लखनऊ में नवनिर्वाचित पार्टी प्रत्याशियों के साथ आयोजित एक संयुक्त प्रेसवार्ता में उन्होंने यह बात कही। इस दौरान सपा नेतृत्व ने एकजुटता का संदेश देते हुए चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को भी मंच पर स्थान दिया। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि इन चुनाव नतीजों ने भाजपा के तमाम राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन के दायरे और प्रभाव को अब और अधिक विस्तार देगी। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को जनसमर्थन से विजय मिली है, जबकि भाजपा ने छह सीटों पर छल-कपट के सहारे जीत दर्ज की है। सपा प्रमुख ने विजयी उम्मीदवारों के साथ-साथ ज़मीनी स्तर

गुजरात में भारत पर्व 2026 का किया शुभारंभ

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में 'स्ट्रेच्चू ऑफ यूनिटी' के पास एकता नगर में 'भारत पर्व 2026' का उद्घाटन किया, जिसमें देश भर की पारंपरिक कलाकृतियां, विरासत और क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने बॉकम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास 'आनंदमठ' पर आधारित एक भव्य नाट्य प्रस्तुति भी देखी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली द्वारा सरदार सोरोवर बांध की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत, 300 कलाकारों वाला यह नाटक 'राष्ट्रीय एकता दिवस' समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। अपने गृह राज्य के दो-दिवसीय दौरे पर आए मोदी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्टॉल मालिकों और शिल्पकारों से बातचीत की। संबंधित कार्यक्रम देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किए गए। वार्षिक 'राष्ट्रीय एकता दिवस' समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देना है।

विश्व कुश्ती में मनीषा गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला

नई दिल्ली। भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने शुक्रवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं के 59 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में अमेरिका की एबिगेल नेट को 8-6 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही मनीषा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। मनीषा ने महिला कुश्ती में इसलिफ भी ख़ास रही, क्योंकि फाइनल मुकाबले में वह एक समय 0-6 से पिछड़ रही थीं। हालांकि, उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अमेरिकी पहलवान को 8-6 से शिकस्त दी और भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाया। मनीषा भानवाला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं। उनसे पहले सुशील कुमार ने साल 2010 में पुरुषों के 66 किलोग्राम भारवर्ग में विश्व खिलाफ जीता था। अब मनीषा ने महिला कुश्ती में यह उपलब्धि हासिल कर भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।



पीएम मोदी की ब्रूसेल यात्रा पक्की

27 देशों के साथ भारत करेगा सबसे बड़ी डील

नई दिल्ली। एक दौर था जब विकासशील देशों को पश्चिमी दुनिया की शर्तों, उनके नियमों और उनके दबाव में समझौते करने पड़ते थे। लेकिन अब 21वीं सदी का यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर बात करता है। अपनी ताकत के बल पर एजेंडे सेट करता है और बायबरी की मेज पर दुनिया के सबसे बड़े गठबंधनों से हाथ भी मिलाता है। आज की भू राजनीतिक हकीकत देखिए। यूरोप ऊर्जा संकट युद्ध के साए और धीमी होती आर्थिक रफ्तार से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत 7% से ज्यादा की जीडीपी विकास दर के साथ पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है। इसी जमीनी हकीकत का नतीजा यह है कि 27 विकसित देशों का संगठन यानी यूरोपीय संघ भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता करने के लिए बेकार है। कनाडा के मॉन्ट्रियल से इस वक्त की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आ रही है। दरअसल यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने सार्वजनिक मंच

से पुष्टि कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर से ठीक पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रूसेल्स पहुंच रहे हैं। मकसद साफ है पीएम मोदी के पहुंचने का भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आधिकारिक और अंतिम दस्तखत करना। यह सिर्फ कागजों पर लिखी इबारत नहीं होगी। यह 2 अरब से अधिक लोगों का एक ऐसा साझा बाजार बनने जा रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के 25वें हिस्से को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।

दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कनाडा के मॉन्ट्रियल से होती है। वहां ईयू कनाडा शिखर सम्मेलन चल रहा था और उसी दौरान मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के एक बड़े कार्यक्रम में एंटोनियो कोस्टा उपस्थित थे। वहां मौजूद थे। जब उनसे वैश्विक व्यापार और यूरोप के भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया और उसमें



भारत का नाम ले लिया। कोस्टा ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में भारत ईयू के ऐतिहासिक ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने ब्रूसेल्स आ रहे हैं। उन्होंने यह बड़ा खुलासा किया। अब इस बयान की टाइमिंग बेहद अहम है। 17 दिसंबर से ब्रूसेल्स में यूरोपीय संघ के तमाम राष्ट्रध्यक्षों और शीर्ष नेताओं की वार्षिक महा बैठक शुरू होने जा रही है वहां पर और वहां बहुत बड़ा मंच लगने जा रहा

है। ठीक उससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना यह दिखाता है कि यूरोप की प्राथमिकताओं में भारत सबसे ऊपर है। सबसे शीर्ष पायदान पर है। इधर नई दिल्ली में भी तैयारियां पूरी रफ्तार पर चल रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि दोनों पक्षों ने तकनीकी बातचीत पूरी कर ली है और इतना ही नहीं समझौते पर हस्ताक्षर होने के मात्र 4 से 5 महीनों के भीतर यह पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि साल 2027 की शुरुआत होते ही भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। वैसे कूटनीति सिर्फ शब्दों से नहीं चलती है बल्कि ठोस आंकड़ों से चलती है और जब आप भारत और यूरोपीय संघ के व्यापारिक आंकड़ों को देखेंगे तो आप अच्छे से बखूबी समझ जाएंगे कि यूरोप भारत के बिना आज क्यों नहीं बह सकता है।

वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में भारत और यूरोप के बीच

गुड्स का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ यानी लगभग 136.54 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत के दबदबे यानी कि ट्रेड सरप्लस की बात करें तो कुल व्यापार में भारत का निर्यात 6.4 लाख करोड़ यानी लगभग 75.85 अरब रहा। जबकि यूरोप से भारत का आयात 5.1 लाख करोड़ यानी लगभग 60.68 अरब डॉलर था। यानी भारत शुद्ध लाभ की स्थिति में है। साल 2024 में दोनों पक्षों के बीच सेवाओं का व्यापार 7.2 लाख करोड़ यानी करीब 83.10 अरब डॉलर दर्ज किया गया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय संघ दूसरी दोनों मिलकर दुनिया की 25वें जीडीपी है और वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप खुद सोचिए जब ये दोनों दिग्गज बाजार शून्य या न्यूनतम टैरिफ पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो उन देशों पर क्या होगा जो अब तक यूरोप में भारतीय सामान को मात देने की कोशिश कर रहे थे।

बारिश से फसल हुई बर्बाद, प्रशासन से किसानों ने की राहत देने की गुहार

■ छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर अब भी बरकरार है.उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है.वहीं मध्य और दक्षिण क्षेत्र में किसान परेशान हैं.

बलरामपुर/कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर अब भी बरकरार है। रायपुर से लेकर बलरामपुर तक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई स्थानों पर रुक-रुककर बारिश की बौछारें हो रही हैं वहीं कई जिलों में बादल छाए हैं। बात करे उत्तर छत्तीसगढ़ की तो यहां सरगुजा,सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज में मौसम बदला हुआ है वहीं कबीरधाम जिले में अर्नब के कारण फसल बर्बाद होने पर कलेक्टर ने सर्वे के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया करने के लिए कहा है।छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग सहित बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बना हुआ है। जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है खेतों में लगी धान की फसल को भी इस बारिश से नुकसान हुआ है। चक्रवाती तूफान अर्नब का असर धमतरी जिले के किसानों पर भी पड़ा है। लगातार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों



की चिंता बढ़ा दी है। चार महीने तक दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार करने वाले किसानों के सामने अब नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। खेतों में पककर तैयार धान की फसल तेज हवाओं के चलते जमीन पर बिछ गई है। तूफानी चक्रवात अर्नब के प्रभाव से पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने कबीरधाम जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं लगातार बारिश के कारण खेतों में पककर तैयार खड़ी धान सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की फसल कटाई के करीब थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने और लगातार बारिश होने से फसलें प्रभावित हो गई हैं। बारिश के कारण खेतों में पानी भरने और फसलों के भीगने से धान,

सोयाबीन सहित अन्य फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है।पहले से ही खेती की लागत और मेहनत से जुझ रहे किसानों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से फसल क्षति का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। कबीरधाम जिले में बड़ी संख्या में किसान खेती-किसानी पर निर्भर हैं। इस साल किसानों ने धान, सोयाबीन और टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार और आमदनी की उम्मीद लगाई थी। फसलें पककर तैयार होने लगी थीं और कटाई का समय भी नजदीक था। इसी बीच बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश का प्रतिकूल असर पड़ने से

साइवलोन अर्नब से बालोद में भी फसलें बर्बाद

बालोद। चक्रवात अर्नब की रफ्तार भले ही दो दिनों की तबाही के बाद अब धीमी पड़ गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद में यह तूफान किसानों के हौसले पूरी तरह पस्त कर गया है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने हजारों एकड़ में खड़ी तैयार फसलों की जमीन पर बिछा दिया है। खेतों में पानी भरा है और बालियां सड़ने की कगार पर हैं। देखिए बालोद के खेतों से यह ग्राउंड रिपोर्ट। बालोद जिले में हजारों एकड़ में लगी धान की फसल इस तूफान की भेंट चढ़ चुकी है। खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। किसानों पर यह दोहरी मार है। पहली फसल गिरने



से दाने काले पड़ने और अंकुरित होकर सड़ने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हावैस्टर या मशीनें अब इन दलदली खेतों में नहीं उतर सकती। ऐसे में फसल

नुकसान का मंजर अब साफ दिखने लगा है। जिले भर के प्रभावित किसान अब उम्मीद की नजरों से प्रशासन की ओर देख रहे हैं। कब राजस्व अमला खेतों में पहुंचेगा और नुकसान का सही आकलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि प्रशासन जल्द कागजी कार्यवाही कर तत्काल गिरादवारी और सर्वे का काम पूरा करे, ताकि फसल बीमा और आपदा राहत की राशि तय वक्त में पहुंच सके। किसानों को इन दिनों कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि कई किसानों की फसलें पानी में पूरी तरह डूबी हुई है।

को बचाने के लिए किसानों को अब महंगे मजदूरों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कटाई का खर्च दोगुना से तीन गुना बढ़ जाएगा। तूफान गुजर चुका है, लेकिन

उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, सब्जी उत्पादक किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर पहले ही काफी खर्च हो चुका है। ऐसे में तैयार फसल खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर

असर पड़ सकता है। कई किसान फसल से होने वाली आमदनी के भरोसे परिवार का खर्च चलाने और कृषि संबंधी कर्ज चुकाने की योजना बना रहे थे लेकिन अर्नब तूफान ने खेती पर पानी फेर दिया। प्रशासन की इस पहल से बारिश की मार झेल रहे किसानों को

राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अब किसानों की नजर सर्वे प्रक्रिया पर टिकी है। किसानों को उम्मीद है कि नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर जल्द राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके।

झंडा दिवस पर बीजापुर पुलिस ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी

■ स्कूली बच्चों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को करीब से समझा

बीजापुर। झंडा दिवस के अवसर पर बीजापुर पुलिस ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान फील्ड वेपन,अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण की प्रदर्शनी को देखने स्कूल के बच्चे भी पहुंचे। बच्चों ने उत्साहपूर्वक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों को देखा और उनकी कार्यप्रणाली, उपयोग की जानकारी ली। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की भूमिका को समझाना था। प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को यह समझने का अवसर मिला कि विषम परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की अंतर्गत सुरक्षा बनाए रखने में आधुनिक हथियारों एवं



उपकरणों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने कई प्रकार के हथियारों और सुरक्षा उपकरणों को लेकर अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल किए। जिनकी जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई। आधुनिक उपकरणों को करीब से देखने का अवसर मिलने से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल निरंतर कार्य करता है। सुरक्षा बलों के पास उपलब्ध आधुनिक हथियार और तकनीकी उपकरण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के बयान पर सियासत गरमाई

■ बेमेतरा में कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने भाजपा और संघ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की



भाजपाइयों ने कराई एफआईआर

बयान पर नाराजगी जताते हुए इसके विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा की। भाजपा नेताओं का कहना था कि सार्वजनिक मंच से राजनीतिक दल के खिलाफ इस तरह की कथित टिप्पणी को लेकर आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है। बैठक के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा के सिग्नल चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गुरुदयाल बंजारे का पुतला दहन कर नारेबाजी की और उनके बयान का विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा

नेताओं ने पूर्व विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू की ओर से बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने में भी शिकायत की गई। शिकायत में देवरबीजा में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बेमेतरा कोतवाली में स्थानीय भाजपा अध्यक्ष ने शिकायत की है

कि नवागढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे उनकी भावनाएं अहत हुई है। इस संबंध में कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है- हरीश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में पूर्व विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक, जब तक गुरुदयाल बंजारे अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा।

सूरजपुर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सील



सूरजपुर। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सील कर दिया गया है। सूरजपुर के तिलसिवां में किए गए के मकान में संचालित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर करीब एक महीने पहले छात्र नेता परमेश्वर राजवाड़े ने कलेक्टर से शिकायत की थी। संस्थान के पंजीयन और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे। छात्र नेता परमेश्वर राजवाड़े ने संस्थान पर आरोप लगाया था कि पैरामेडिकल काउंसिल रायपुर में पंजीयन नहीं होने के बावजूद यहां डीएमएलटी और बीएमएलटी जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा डीएमएलटी

एवं बीएमएलटी के विद्यार्थियों से फीस लेने के बावजूद उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल पाया। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान के संचालन में अनियमितताएं सामने आने के बाद कलेक्टर के हस्तक्षेप पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रशांत सिंह, तहसीलदार और नर्सिंग हाथम एक्ट के नोडल अधिकारी की मौजूदगी में गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में है। अब देखना होगा कि प्रभावित विद्यार्थियों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है

सूरजपुर में 8 टीआई, 2 एसआई का हुआ तबादला

सूरजपुर। एसपी योगेश पटेल ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से 8 निरीक्षक, 2 एसआई, 8 एएसआई के अलावा 55 प्रधान आरक्षक व आरक्षक का तबादला कर दिया। एसपी ने सभी को तत्काल संबोधित था-चौकी में ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए। जिन निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें रंजीत प्रताप सिंह को रक्षित केंद्र से शिकायत शाखा प्रभारी, नंद किशोर गौतम को रक्षित केंद्र से रीडर टू एसपी, रमेश पटेल को थाना प्रभारी रामानुजगंज, सत्यनारायण देवांगन को थाना प्रभारी रमकोला, मिलन सिंह को थाना प्रभारी चांदनी, ढाल सिंह साहू को थाना प्रभारी जयनगर, रुपेश कुंतल एक्का को साइबर सेल प्रभारी व जावेद मितांदाद को डीसीबी/डीसीआरबी से प्रभारी डीसीबी/डीसीआरबी बनाया है। इसी प्रकार एसआई अमित कुमार गुप्ता को थाना प्रभारी जयनगर से बसदेई चौकी प्रभारी व हीरालाल साहू को थाना प्रभारी रमकोला से सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ किया गया है। उनमें अरुण गुप्ता को साइबर सेल सूरजपुर से चौकी प्रभारी करंजी, अमरेश सिंह को साइबर सेल सूरजपुर में स्थानान्तरित किया।

एनएमडीसी ने बाढ़ प्रभावितों को 400 तिरपाल वितरित किए

जगदलपुर। जिले के इंद्रावती नदी के आस-पास के गांवों में भारी जलभराव हुआ तथा कई परिवारों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वाले परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु एनएमडीसी ने 18म24 फीट के उच्च गुणवत्ता वाले तिरपाल वितरित किए जा रहा है। एनएमडीसी की इस पहल का तक्ररीबन एक हजार ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलेगा। आज 29 अक्टूबर 2026 को एनएमडीसी के ईडी एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप द्वारा कुप्पाल गांव में 200 तिरपाल वितरित किए गए। वहीं बड़े चकवा ग्राम पंचायत एवं घाटगनौरा गांव (जनपद पंचायत बस्तर) में भी 200 तिरपाल वितरित किए गए। प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु 600 तिरपालों का वितरण प्रस्तावित है।बस्तर सांसद महेश कश्यप ने एनएमडीसी की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि चक्रवाती तुफान से हाल ही में आये बाढ़ की आपदा से निपटने में एनएमडीसी ने विशेष भूमिका निभाई और बस्तरवासियों के लिए एक मजबूत सहारा बन कर सामने आयी।

मुफ्त राशन की व्यवस्था में 5798 संदिग्ध मिले

जगदलपुर। बस्तर जिले में गरीबों को मिलने वाले सरसे और मुफ्त राशन की व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 13 हजार संदिग्ध लोगों के लाभ लेने का मामला डेटा की डिजिटल जांच में मिले हैं। इनमें आधार संबंधी विसंगतियां, डुप्लीकेट नाम, आयकरदाता, ईपीएफओ से जुड़े नौकरपेशा लोग और सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। ब्लॉकवार आंकड़ों में कावर्ड 5,798 संदिग्ध रिकॉर्ड के साथ बस्तर ऊपर है। जगदलपुर ग्रामीण में 3,295, बस्तर ब्लॉक में 2,699, बास्तानगर में 956 और बस्तर शहरी क्षेत्र में 217 रिकॉर्ड मिले हैं। इन आंकड़ों के आधार पर मैदानी स्तर पर सत्यापन करना प्रशमन के सामने बड़ी चुनौती होगी। जांच में सामने आए इन आंकड़ों ने सवाल खड़ा किया है, कि पात्रता की शर्तों के बावजूद ऐसे नाम राशन कार्डों की सूची में कैसे शामिल हुए। क्या इनके जरिए सरकारी राशन का अनुचित लाभ लिया जा रहा था। डेटा मिलान में मिली विसंगतियों के बाद अब प्रशासन इन सभी मामलों का ब्लॉकवार सत्यापन करवा रहा है।

दंतेवाड़ा में पुरुष से दुगने महिला खिलाड़ियों का हुआ पंजीयन

दंतेवाड़ा। बस्तर ओलंपिक 2026 में भाग लेने के लिए दंतेवाड़ा जिले से अब तक 70 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। खास बात यह है कि इस बार महिला खिलाड़ियों की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कुल 70,460 खिलाड़ियों का पंजीयन कराया गया है, जिनमें 46,949 महिला और 23,513 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। बस्तर ओलंपिक 2026 के पंजीयन आंकड़ों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महिलाओं की यह भागीदारी बताती है कि बस्तर अंचल में खेलों के प्रति रुचि केवल पुरुष खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आगे आ रही हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पंजीयन अभियान संचालित किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

बस्तर में कटे पेड़ों की भरपाई के क्षतिपूर्ति पौधरोपण योजना बंद

जगदलपुर। रियासत कालीन बस्तर दशहरा में प्रति वर्ष एक नये रथ निर्माण की परंपरा के निर्वहन के लिए हर साल सैकड़ों पुराने पेड़ काटे जाते है, लेकिन अब उनके बदले पौधे लगाने की तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। बस्तर दशहरा के विशाल रथ के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष लगभग सैकड़ो पुराने पेड़ों की कटाई की जाती है, इसके आड़ में भी बड़ा वारा-न्यारा होने की बात को नकारा नही जा सकता। परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्षतिपूर्ति पौधरोपण को आयोजन का स्थायी हिस्सा बनाने की जरूरत है। अन्यथा न परंपरा बचेगी और न ही पर्यावरण बचेगा। पिछले पांच वर्षों से बस्तर दशहरा समिति और वन विभाग ने मिलकर अलग-अलग स्थानों पर पौधरोपण कराया। कुमड़ाकोट जंगल, मारकेल के बोदामुंडा और नकटी सेमरा जैसे स्थानों पर इस दिशा में पहल की गई थी। लेकिन दशहरा 2026 संघर्ष होने के बाद अब तक क्षतिपूर्ति पौधरोपण को लेकर कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। पर्यावरण संरक्षण समितियों के सदस्यों को आशंका है।

सामूहिक नेतृत्व में 2028 का चुनाव: नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत

■ 1 नवम्बर को दिल्ली में वोट बचाओ देश बचाओ आंदोलन में जांजगीर चांपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

जांजगीर चांपा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मांग की कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए। महंत ने कहा कि उन्हें ईवीएम से शिकायत है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में तंत्र मंत्र करती है जिससे हर आठवां- 10वां वोट उनके खते में चला जाता है। महंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रति विधानसभा क्षेत्र लगभग 5 करोड़ रुपये लेती है और हेराफेरी करती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ही कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण टीएएस सिंहदेव है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 94 वोटों से हारे थे। महंत ने आगे कहा कि देश में तानाशाह शासन का वातावरण बन रहा है। अस्थिरता है, लोकतंत्र के साथ ही संविधान को खतरा पैदा हो गया है, जिसे गांधी परिवार ही बचा सकता है। आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सोचकर हम इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। हमारी पहचान छिनी



जा रही है। हमारे वोट की कीमत आज कुछ नहीं रह गई है। अक्सर चुनाव से एक महीने पहले वोटर लिस्ट देखते थे, लेकिन अब कांग्रेस मतदाता सूची का गहन परीक्षण करने के बाद गलती को बता रहे हैं। महंत ने कहा कि देश में 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। फॉर्म 6 के नाम से भी वोट काटे गए। धर्म के नाम पर वोट काटे गए हैं। एससी एसटी, ओबीसी, मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों का जवाब वो खुद ना देकर बीजेपी दे रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस

के प्रदेश पर्यवेक्षक शरद आहिरे ने बीजेपी को क्रिमिनल माइंडेड पार्टी बताया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए हर चुनाव में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। प्रदेश पर्यवेक्षक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बाप को भी जाना पड़ेगा वाले बयान को बोलचाल की भाषा बताया, और नरेंद्र मोदी अमित शाह द्वारा राहुल गांधी के परिवार पर की गई टिप्पणी को बीजेपी की कुटित मानसिकता बताया।बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए वोटर्स का नाम कटने में सीईसी ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका होने की भी बात कांग्रेस नेता ने कही। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। वोट बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ वोटर्स को दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश पर्यवेक्षक शरद आहिरे, संगठन सह प्रभारी विजय जांगिड़ और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत हर जिले में जाकर वोट बचाओ देश बचाओ का आह्वान कर रहे हैं।

बिलासपुर। राजस्व कार्य के लिए रिश्तत मांगना और लेना भारी पड़ गया। रिश्तत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्यवाई करते हुए पटवारी को निर्लंबित कर दिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपये की रिश्तत मांगने और लेने के मामले में पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर दिया है। पटवारी का रिश्तत मांगने और लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्यवाई करते हुए पटवारी को निर्लंबित करने का आदेश जारी किया। आदेश में पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत एवं गंभीर कदाचरण की



गोस्वामी पहले हल्का नंबर 14 में पदस्थ था। वर्तमान में तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत हैं। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर 2026 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद कलेक्टर ने पटवारी को निर्लंबित करने का आदेश जारी किया। आदेश में पटवारी के कृत्य को विपरीत एवं गंभीर कदाचरण की

श्रेणी में मानते हुए शासन की छवि धुिलत करने वाला बताया गया है। निर्लंबन अवधि में गोस्वामी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

संक्षिप्त समाचार

सीएम साय ने फसल क्षति का सर्वे कर शीघ्र मुआवजा देने का दिया निर्देश

रायपुर। चक्रवात ‘अर्नब’ की वजह से नुकसान झेलने वाले प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तमाम कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कर प्रभावित किसानों को शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में कहा कि चक्रवात ‘अर्नब’ से फसलों को हुए नुकसान के कारण हमारे अन्नदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने और प्रभावित किसानों को आर ली सी। 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भते की राशि का भुगतान नवंबर 2026 से देय होगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। आदेश के मुताबिक, महंगाई भते के भुगतान के दौरान यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि होती है तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालाँकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भते के तहत किया जाने वाला भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

माय भारत, रायपुर द्वारा दिशा कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर। मेरा युवा भारत रायपुर द्वारा दिशा कॉलेज, रायपुर में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 250 से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में यूथ आइकन सुयश पांडे तथा सपोर्ट्स आइकन लक्ष्मी पटेल भी शामिल हुए। अग्रवाल ने युवाओं को लोकतंत्र के महत्व से अवगत कराया तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से संवाद स्थापित कर उनके विचारों, सुझावों और जिज्ञासाओं को सुना। इस दौरान युवाओं ने लोकतंत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और अनेक प्रश्न पूछे। सांसद महोदय ने उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ रद्द

रायपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता काशी बाई का आज 76 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके साथ ही उनका शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्री की माता के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक जताते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार, शिवराज सिंह की माता का भोपाल एम्स में उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार ग्राम जैत, सीहोर में होगा। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक जताते हुए दुःख की इस घड़ी में अपनी गहरी संवेदनाएँ शिवराज सिंह एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के प्रति व्यक्त की।

ई-रिवशा ने बदली संगीता देवी की ज़िंदगी, स्वरोजगार से बनीं लखपति दीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विहान और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के सहयोग से महिलाएं पारंपरिक आजीविका गतिविधियों से आगे बढ़कर नए व्यवसायों में अपनी पहचान बना रही हैं। जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड की ग्राम पंचायत छेरडाढ़ निवासी श्रीमती संगीता देवी इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। कभी परिवार की जरूरतों और कृषि कार्यों के लिए स्व-सहायता समूह से छोटे-छोटे ऋण लेने वाली संगीता आज स्वयं ई-रिवशा चलाकर प्रतिमाह 15 से 18 हजार रुपये की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने लखपति दीदी बनने का सफर तय किया है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों में लाई जाए तेजी: मुख्य सचिव

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण, 15 नवंबर से पहले फसलों की गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निराकरण के पश्चात इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

15 नवंबर तक गिरदावरी कार्य पूरा करने के निर्देश

राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के



दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 15 नवंबर से पूर्व सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा कर लिया जाए। इसकी जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के

खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो वे ग्राम सभा में आवेदन देकर तत्काल इसे पूर्ण करवा सकते हैं।

निर्माण कार्यों में गति लाने पर जोर

बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए लोक निर्माण विभाग ने

शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूरा किया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। पंचायत

एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों की शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए एक सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना पर कार्य करने को कहा गया। बैठक के दौरान संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों की भी विस्तृत जानकारी ली गई।

पारस पोर्टल और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा

बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना में बिना किसी विलंब के प्रगति लाने के निर्देश

दिए गए। इसके साथ ही, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं एवं प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्योत्सव में दिखेगी विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर

सरगुजा में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर को सरगुजा जिला मुख्यालय में एक दिवसीय राज्योत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरगुजा जिले में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

राज्योत्सव 2026 की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कार्यक्रम स्थल पर महिला सशक्तीकरण, युवाओं के अवसरों और प्रदेश के समग्र विकास को केंद्र में रखकर आयोजन किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा विकास योजनाओं,



महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफल परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी मिल सकेगी।

जिला स्तरीय राज्योत्सव में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही, शासन की कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितप्राहियों को लाभान्वित करने की भी व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रमों में शालीनता और गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य स्थापना दिवस

का आयोजन उत्साहपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक सरगुजा जिला मुख्यालय स्थित शासकीय भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने बजट से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

सरगुजा में आयोजित होने वाला राज्योत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का अवसर होगा। ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की थीम के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और युवा सहभागिता के महत्व को भी रेखांकित किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता से सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और समान नागरिक अधिकारों को मिलेगी मजबूती

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी और जनसंवाद का क्रम जारी है। इसी कड़ी में स्वयंप्रभा फाउंडेशन एवं आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। समान नागरिक संहिता

समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिकता श्री मोहन पवार ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। समिति की ओर से सुझावों के समुचित परीक्षण एवं विचार-विमर्श के दौरान उन्हें संज्ञान में लेने की बात कही गई। प्रतिनिधियों ने विक्ष्वस व्यक्त किया कि व्यापक जनभागीदारी और विभिन्न समुदायों के विचारों के आधार पर तैयार की जाने वाली समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

प्रतिनिधियों ने सुझाव प्रस्तुत किया कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार, महिलाओं को न्यायपूर्ण संरक्षण और समाज में समानता एवं समरसता को



बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। स्वयंप्रभा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिव नारायण मुंदड़ा, डॉ. मुकेश शाह तथा आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के अध्यक्ष श्री इन्द्रनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति एवं पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कानूनों में समानता स्थापित होने से नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी, इससे कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी।

प्रतिनिधियों ने महिलाओं के अधिकारों को विशेष प्राथमिकता देते हुए

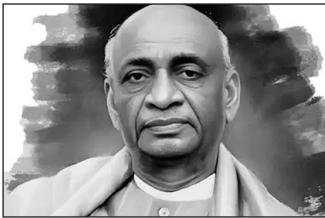
कहा कि बहुविवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं, भरण-पोषण संबंधी असमानताओं और संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव को दूर करने की दिशा में प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए। विशेष रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार तथा महिलाओं को विवाह और तलाक के मामलों में न्यायपूर्ण संरक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराएं हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले इनकी परंपराओं, सामाजिक हितों और संवैधानिक संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

नविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)		
एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु. (लाख में)
एन.आई.टी. क्र./सिस्टम टेन्डर नं.		
1	2	3
223/202778	उपसंभाग क्र.-1 के अंतर्गत माना सेक्शन के विभिन्न सड़कों में विशेष मरम्मत कार्य।	रु. 21.18 लाख
221/202779	S/R, MOW, Deposit And Other Work Of Various Roads Arang Section Under Sub-Division Survey Raipur (C.G.)	रु. 20.50 लाख
225/202780	उपसंभाग क्र.-1 के अंतर्गत रोड सेक्शन के विभिन्न सड़कों में विशेष मरम्मत कार्य	रु. 21.18 लाख
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.11.2026 समय सायं 5:30 बजे तक उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विवरित, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।		
अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभा रायपुर मंडल क्र1 रायपुर (छ.ग.)		
जी-262704271/2		

अखंडता का संकल्प: सरदार पटेल और मजबूत भारत का सपना

रायपुर। भारत की पहचान उसकी विविधता और एकता में है। यहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं का पालन किया जाता है, फिर भी देशवासियों को एक सूत्र में बाँधने वाली भावना है-राष्ट्रीय एकता। यह एकता केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात से भी जुड़ी है कि हर नागरिक स्वयं को देश के सझा भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करे। हर वर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करने के साथ-साथ आज के भारत में एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी का



एहसास कराता है।

वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता के समय भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं। अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वी. पी. मेनन और अन्य अधिकारियों के सहयोग से संवाद, समझदारी और दृढ़ नेतृत्व के माध्यम से रियासतों के एकीकरण की

प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिन्होंने 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय कर देश को एक सूत्र में

पिरोया। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने तथा आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों को सामना करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत किया। सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों ने एक मजबूत और एकीकृत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2014 से उनका जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर %रन फॉर यूनिटी’, राष्ट्रीय एकता की शपथ और विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया जाता है। सरदार पटेल की विरासत हमें सिखाती है कि विभिन्न विचारों, हितों और पहचानों के बीच

तालमेल बनाकर ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

आज भारत के सामने चुनौती रियासतों को एकजुट करने की नहीं, बल्कि विकास के लाभों को देश के प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक तक पहुँचाने की है। सड़क, रेल, बिजली, संचार और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार दूरस्थ क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। इससे लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। हालाँकि, केवल बुनियादी ढाँचे का विकास ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर मिलें, सार्वजनिक सेवाएँ सुलभ हों और उनकी आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाए।

विधान परिषद के नतीजे भविष्य की इमारत के संकेत?

अकू श्रीवास्तव

आमतौर पर यह माना जाता है कि बड़े चुनाव के पहले जो चुनाव होता है और उसके जो नतीजे होते हैं, वे एक तरह से आने वाले दिनों का आईना होते हैं। लेकिन क्या यह बात उत्तर प्रदेश को लेकर भी कही जा सकती है ? यू.पी. में विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष शुरुआती महीनों में होने हैं और 29 अक्तूबर को जब विधान परिषद की कुछ सीटों (उत्तर प्रदेश की सिर्फ 11 सीटों के चुनाव हुए थे जबकि कुल सीटें 100 हैं) के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीतीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने आखिरकार 5 सीटें जीतने में सफलता पा ली। भाजपा के पास पहले भी 6 सीटें थीं लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 3 ही सीटें थीं। बाकी 2 सीटें निर्दलीयों के पास थीं, जो इस बार समाजवादी पार्टी ने छीन लीं। इस चुनाव में भाजपा ने भी इन निर्दलीयों की सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश की ही थी लेकिन सफलता मिली समाजवादी पार्टी को। इस सफलता को कैसे देखा जाए ? पहले तो समझते हैं, विधान परिषद के चुनावों की। देश में पहले कई राज्यों में विधान परिषदें थीं। विधानपरिषदों का गठन वैसे ही किया गया था जैसे लोकसभा के साथ राज्यसभा का गठन हुआ था। विधान परिषद को राज्यों का उच्च सदन भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का सुजन या फिर गठन तभी हो सकता है जब राज्य की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव दे। बोते 5 दशकों में राज्यों की सरकारों ने खर्च कम करने के नाम पर विधान परिषदों को खत्म करने का सिलसिला किया। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद बची हैं, जबकि 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इसे फिर से बनाने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन संसद से इसे अंतिम मंजूरी लंबित है। पंजाब में भी पहले विधान परिषद थी, जिसे 1970 में समाप्त कर दिया था। विधान परिषद के लिए एक-तिहाई लोगों का चयन विधायक और इतने ही लोगों का चयन स्थानीय निकाय करते हैं, जबकि 1/12 सीटों का चुनाव स्नातक-शिक्षक करते हैं और बाकी लोगों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। हालिया चुनाव यू.पी., बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से हुआ था। शिक्षकों-स्नातकों की अलग से मतदाता सूची बनती है। यूं तो यह दलों के आधार पर नहीं होते लेकिन राजनीतिक दल समर्थित होते हैं। अब तो राजनीतिक दल टिकट बांटे हैं। बाकायदा सूची जारी होती है। इस बार भी हुई। चुनाव बैलेट पैपर से होते हैं और प्रिफ़रेंशियल वोटिंग होती है (राज्यसभा चुनावों की तरह)। कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को बड़ा झटका लगा और कांग्रेस एक भी सीट नहीं ले सकी। एन.डी.ए. को चारों सीटें मिलीं। बिहार में बड़ा उलटफेर दिखा। भाजपा को 3, राजद को 2 तथा जे.डी.यू., जनसुसुज व निर्दलीय को 1–1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर चुनाव हुए और महायुति ने कमाल किया लेकिन अंतिम एक नतीजा आखिरकार कांग्रेस के पक्ष में आ ही गया। नागपुर की यह सीट भाजपा के लिए झटका जरूर माना जा रहा है। मगर सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों की है। नतीजे बताते हैं कि यह समाजवादी पार्टी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से बड़े बदलाव लेकर आए। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद में सपा के पास पहले 10 सदस्य थे और यदि पार्टी 3 से कम सीटें जीतती, तो उससे नेता प्रतिपक्ष का पद छिन सकता था। लेकिन अब उसके सदस्यों की संख्या 12 हो जाएगी और उससे बड़ी बात यह है कि उसकी वह जीत ऐसे समय पर आई है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

21. तथाकथित सौत्रान्तिक दर्शन सम्प्रदाय

गतांक से आगे...

एक कठिनाता और भी है दिङ्नाग सम्प्रदाय महायान के अन्तर्गत है और सौत्रान्तिक हीनयान के अर्न्तगत समझा गया था। ऐसी दशा में हम ने सौत्रान्तिक को मुख्य दर्शन विभागों में नहीं रक्खा, और दिङ्नाग सम्प्रदाय को एक अलग सम्प्रदाय के रूप में दिखाया है।

22. नागार्जुन का शून्यवाद

शून्यवाद साहित्य-कालक्रम की दृष्टि से सर्वास्तिवाद के बाद नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद आता है। शून्यवाद के साथ ही बौद्ध इतिहास में महायान युग प्रारम्भ होता है। अथवा यह कहा जा सकता है महायान रूप में हुये बौद्ध धर्म के नये विकास का ही दार्शनिक पहलू शून्यवाद है। महायान सम्प्रदाय वाले बौद्ध थेरावादि ?यों के पाली त्रिपिटक को नहीं मानते।

सर्वास्तिवादियों के समान महायान का अपना

कोई अलग द्त्रिपिटक नहीं है। परन्तु 1 महायान सूत्र जो 6 धर्म कहे जाते हैं और जिन्हें वैपुल्यसूत्र भी कहते हैं, महायान सम्प्रदाय के आधार भूत ग्रन्थ हैं। यहां धर्म शब्द धर्मपर्याय शब्द का संक्षेप मात्र है धर्मपर्याय का अर्थ है धर्मसम्बन्त्री ग्रन्थ । निम्नलिखित. 6 धर्म महायान सम्प्रदाय में स्वीकार किये गये हैं-

- अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता।
- सद्धर्मपुण्डरीक।
- ललितविस्तर।
- लङ्कावतार या सद्धर्मलङ्कावतार।
- सुवर्णप्रभास।
- गण्डव्यूह।
- तथागत गुह्यक या तथागत गुणज्ञान।
- समाधिराज।
- दशभूमीश्वर।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

वोट चोरी का नैरेटिव और सांगठनिक विफलता का असली आईना

अशोक भाटिया

भारतीय लोकतांत्रिक विमर्श में पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब और गहरी चिंताजनक परिपाटी देखने को मिल रही है। देश के राजनैतिक दल अपनी सांगठनिक कमजोरियों, जमीन से कटते जा रहे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच नीतियों के गहरे संकट पर आत्ममंथन करने के बजाय, अपनी हर पराजय का पूरा ठीकरा देश की संवैधानिक चुनावी व्यवस्था पर फोड़ देते हैं। इस पूरे राजनैतिक खेल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को एक बड़े वैश्विक खलनायक के रूप में पेश किया गया। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने एक सुर में %वोट चोरी% का एक ऐसा आक्रामक और संदेहास्पद नैरेटिव गढ़ा, जिसने आम मतदाताओं के मन में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास के बीज बोने की पुरजोर कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर पर महीनों तक इस बात का माहौल बनाया गया कि यदि देश को वापस मतपत्र यानी पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली के दौर में ले जाया जाए, तो लोकतंत्र का खोया हुआ गौरव और निष्पक्षता रातों-रात बहाल हो जाएगी।

लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह अपने शांत मगर अचूक और ऐतिहासिक फैसलों से बड़े-बड़े राजनैतिक ढोंग, खोखले दावों और हवा-हवाई नैरेटिव की कलाई खोलकर रख देता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों पर पूरी तरह बैलेट पेपर से हुए चुनावों के परिणाम किसी भी गंभीर राजनैतिक विश्लेषक के लिए आंखें खोलने वाले हैं। जब चुनावी खेल पूरी तरह से कांग्रेस की मनपसंद मतपत्र प्रणाली से खेला गया—जहां न तो कोई माईक्रोचिप थी, न कोई सॉफ्टवेयर था, न कोई प्रोग्रामिंग थी और न ही तकनीक का कोई अदृश्य हस्तक्षेप था—तब भी कांग्रेस को मिला करारा सांगठनिक झटका यह अकाट्य रूप से साबित करता है कि समस्या मशीनों की तकनीक में नहीं, बल्कि पार्टी की बुनियादी राजनीति, नीयत और धरातल में है।

23 अक्टूबर को देश के चार बड़े और राजनैतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों पर मतपत्रों के जरिए वोट डाले गए थे। 27–28 अक्टूबर को जब मतपेटियां खुलीं, तो चुनावी भूगोल की एक बिस्कुल नई और अप्रत्याशित तस्वीर सामने आई। यह चुनाव कोई आम जनता या आम जनसभाओं का



पारंपरिक चुनाव नहीं था, बल्कि यह विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का विशेष चुनाव था। इन चारों राज्यों का संघुर्ण चुनावी परिदृश्य कांग्रेस के दावों की जमीनी हकीकत को बयां करता है—

पहले कर्नाटक की बात करें—यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा, ऐतिहासिक और सबसे आत्मघाती झटका रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सिद्धार्थैया सरकार होने के बावजूद, बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव में भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने बाजी मार ली। बेंगलुरु टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा-जेडीएस के एपी रंगनाथ ने सिटिंग एमएलसी पुट्टुडा को करारी शिकस्त दी, वहीं वेस्ट ग्रेनुएट्स सीट पर भाजपा के एस.वी. संकनूर ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस के मोहन लिम्बिकाई को 9,323 मतों के बहुत बड़े अंतर से पराजित किया। जब सत्ताधारी दल अपने ही राज्य में मतपत्रों से हार जाए, तो दोष किसे दिया जाए?

बिहार की शिक्षक और स्नातक सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर दयनीय और निराशाजनक रहा। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रशांत किशोर की नवगठित जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश राय ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को करारी शिकस्त देकर राज्य के राजनैतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यहां तक कि मतपत्रों के दौर में भी कांग्रेस अपने पुराने नेताओं की साख नहीं बचा पा रही है।

उत्तर प्रदेश में वजूद का संकट उभर आया। यहाँ की 11 सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच ही सिमत कर रह गया। मेरठ जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और वाराणसी में सपा ने अपना दमखम दिखाया, जबकि कांग्रेस इस पूरे मतपत्र वाले चुनाव में कहीं भी रस में दिखाई नहीं दी।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और विशेषकर कांग्रेस के लिए राहत की बात केवल यह रही कि नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में

सदैव सादगी भरा रहा सरदार पटेल का जीवन

भीतर और न ही किसी अन्य की इतनी हिम्मत हुई कि वह बच्चे को सलाख से दागने की हिम्मत जुटा सके। आखिरकार अविचलित बने रहकर सरदार पटेल ने स्वयं ही लोहे की सलाख को गर्म करके फोड़े पर लगा दिया, जिससे वह फूट गया और कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। उनके इस अद्भुत साहस को देखकर पूरा परिवार और आस-पड़ोस के लोग अर्चभित रह गए।

1909 में जब वे वकालत करते थे, उस दौरान तो उनकी कर्तव्यपरायणता की मिसाल देखने को मिली, जिसकी आज के युग में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस समय उनकी पत्नी झावेर बा कैसर से पीड़ित थी और बम्बई के एक अस्पताल में भर्ती थी लेकिन अपरेशन के दौरान उनका निधन हो गया। उस दिन



सरदार पटेल अदालत में अपने मुक्किल के केस की पैरवी कर रहे थे, तभी उन्हें संदेश मिला कि अस्पताल में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। संदेश पढ़कर उन्होंने पत्र को चुपचाप जेब में रख लिया और अदालत में अपने मुक्किल के पक्ष में लगातार दो घंटे तक बहस करते रहे। आखिरकार उन्होंने अपने मुक्किल का केस जीत लिया। केस जीतने के बाद जब न्यायाधीश सहित वहां उपस्थित अन्य लोगों को मालूम हुआ कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है तो उनकी पत्नी ने सरदार पटेल से पूछा कि वे तुरंत अदालत की कार्रवाई छोड़कर चले क्यों नहीं गए? पटेल ने जवाब दिया कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुक्किल ने न्याय पाने के लिए चुका दिया था और मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता था।

सरदार पटेल का पूरा जीवन सादगी से

भोजन ही ग्रहण किया करते थे। एक बार उनका संत विनोबा भावे के आश्रम में जाना हुआ, जहां रसोई में उत्तर भारत के किसी गांव से आया एक साधक भोजन व्यवस्था के कार्य से जुड़ा था। सरदार पटेल को आश्रम का विशिष्ट अतिथि जानकर साधक ने उनसे पूछा कि आपके लिए रसोई पक़ी बनेगी या कच्ची? सरदार पटेल उसका आशय नहीं समझ सके तो उन्होंने साधक से इसका अभिप्राय पूछा। तब साधक ने उनसे पूछा कि वे कच्चा खाना खाएंगे या पक़ा? यह सुनकर सरदार पटेल ने कहा कि कच्चा क्यों खाएंगे, पक़ा खाना ही खाएंगे। जब खाना बनने के पश्चात् उनकी थाली में पूरी, कचौरी, मिठाई इत्यादि चीजें परोसी गईं तो सरदार पटेल ने सादी रोटी और दाल की मांग की।

आज का इतिहास

- 1759 फिलीस्तीन के साफेद में भूकंप से 100 लोग मारे गये।
- 1864 नेवादा अमेरिका का 36वां प्रांत बना।
- 1905 अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रांतिकारी प्रदर्शन।
- 1908 चौथे ओलंपिक खेलों का लंदन में समापन।
- 1914 ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1920 मध्य यूरोपीय देश रोमानिया ने पूर्वी यूरोप के बेसारबिया पर कब्ज़ा किया।
- 1953 बेंलुजियन में टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ।
- 1956 स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू की।
- 2003 सोवियत संघ तथा मिस्र ने नील नदी पर अस्वान बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 1960 बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से करीब दस हजार लोगों की मौत।
- 1966 भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया।
- 1978 ईरान में तेल कर्मचारियों की हड़ताल शुरू
- 1978 यमन ने अपना संविधान अंगीकार किया।
- 1982 पोप जॉन पॉल द्वितीय स्पेन जाने वाले पहले बिशप बने।
- 1984 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पश्चात् राजीव गांधी भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने।
- 1989 दुर्गत ओजल तुर्की के राष्ट्रपति चुने गये।
- 1996 रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की मंजूरी मिली।
- 2003 हैदराबाद में आयोजित अफ़्‌रोएशियन हॉकी चैम्पियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3–1 से हराकर स्वर्ण प्राप्त किया।
- मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहतिर मोहम्मद ने शासन की बागडोर उपप्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद को सौंपी।
- 2003 मलेशियाई प्रधानमंत्री महाशिर मुहम्मद के 22 वर्ष लंबे शासन का अंत हुआ।
- 2005 फिलिस्तीन-इस्रायल हिंसा न करने पर सहमत। रूस को वोल्कर रिपोर्ट के पीछे जोड़-तोड़ का सन्देह। चीन और नेपाल सीमा के संयुक्त निरीक्षण पर सहमत।
- 2006 श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों पर जाफना प्रायद्वीप में जवानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया।
- 2008 देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने सम्बन्धी विधेयक को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने मंजूरी दी।

यूरोप में उत्तरप्रदेश के ‘योगी मॉडल’ पर अमल के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

कमलेश पांड

यूरोप में कानून-व्यवस्था, हिंसक प्रदर्शनों, संगठित अपराध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन-शैली पर चर्चा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत विषय है। लेकिन इसका विश्लेषण करते समय एक बुनियादी सवाल समझना आवश्यक है कि क्या यूरोप को यूपी के %योगी मॉडल% की सख्ती अपनाने की जरूरत है, या उसे उस मॉडल के कुछ चुनिंदा प्रशासनिक उपायों से सीख लेनी चाहिए ? यहां पर यह बुनियादी सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2017 के बाद अमेरिका-यूरोप ने योगी मॉडल की आलोचना की थी!

लिहाजा, इस प्रश्न का उत्तर यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, मानवाधिकार संबंधी प्रतिबद्धताओं और उत्तर प्रदेश में अपनाई गई नीतियों के वास्तविक परिणामों को साथ रखकर ही दिया जा सकता है। लेकिन जब इस्लामिक अतिवादी स्थानीय असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर यूरोप का इस्लामीकरण पर उतारू हों और ईरान का परोक्ष बरदहस्त उन्हें प्राप्त हो तो अमेरिका के बाद यूरोपीय विवशता समझी जा सकती है।

सबसे पहला सवाल यह है की ‘योगी मॉडल’ से हमारा आपका क्या आशय है ? तो माकूल जवाब यही होगा कि राजनीतिक विमर्श में ‘योगी मॉडल’ का प्रयोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देने, अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई, संगठित अपराध पर नियंत्रण, प्रशासनिक सख्ती और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसी नीतियों के लिए किया जाता है।

हालाँकि, इन सभी उपायों को एक ही श्रेणी में रखना

उचित नहीं है। अपराध की जाँच, दोषसिद्धि, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। चूँकि यूपी में बेलगाम अल्पसंख्यक अपराधियों, सत्ता संरक्षित बाहुबलियों, इनसे जुड़े मनबद्ध युवाओं और शांतिर अपराधियों के इशारे पर अपराध कर रहे बहुसंख्यक अपराधियों को नियंत्रित करने में यूपी के योगी मॉडल ने आशातीत सफलता प्राप्त की है, इसलिए चारो तरफ से जल रहे फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देशों के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। सर्वप्रथम इटली की प्रमुख और मोदी की मित्र जॉर्जिया मेलोनी ने यूपी के योगी मॉडल पर अमल करने की घोषणा की, तत्पश्चात मोदी के दूसरे मित्र फ्रांस के प्रमुख मैक्रो ने जब यूपी के योगी मॉडल की अच्छी नीतियों पर अमल करना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गैंग सक्रिय हो गया और यूरोपीय देशों को उस नकारा लोकतंत्र की दुहाई देने लगा, जहां के बेलगाम लोग जुल्मी पूंजीवादी अड्डों को फूँकने के बजाय अपने देश के सार्वजनिक जगहों, नागरिक सुविधाओं और ठिकानों को ही फूँक रहे हैं !

यूरोप में इस मॉडल की चर्चा के तीन संभावित कारण हैं–

एक, कानून का प्रभावी प्रवर्तन: हिंसा, लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई करना।

दो, प्रशासनिक जवाबदेही: पुलिस और स्थानीय प्रशासन की तैयारी, समन्वय तथा निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना।

तीन, राज्य की विश्वसनीयता: नागरिकों को यह भरोसा दिलाना कि शांतिपूर्ण जीवन, सार्वजनिक परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा सरकार की



जिम्मेदारी है। लेकिन किसी मॉडल का प्रभाव उसके नाम या राजनीतिक लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उसके परिणामों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन से मापा जाना चाहिए।

दूसरा प्रासंगिक सवाल यह है कि यूरोप के लिए इसके क्या अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ हो सकते हैं ?

एक, कानून-व्यवस्था की बहस में बदलाव: यदि यूरोपीय देश उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गति, पुलिस-प्रशासन के समन्वय और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, तो उनकी आंतरिक सुरक्षा नीतियों में बदलाव आ सकता है। इससे भारत के प्रशासनिक अनुभवों में अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ सकती है।

दो, भारत की सॉफ्ट पावर और नीतिगत प्रतिष्ठा: भारत के किसी राज्य की प्रशासनिक नीति पर यूरोप में गंभीर चर्चा होना भारतीय संघीय व्यवस्था के अनुभवों को आंतरिक सुरक्षा नीतियों में बदलाव आ सकता है। इससे भारत के प्रशासनिक अनुभवों में अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ सकती है।

तीन, मानवाधिकार और कानून के शासन पर बहस: यूरोप में पुलिस कार्रवाई के साथ नागरिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और न्यायिक समीक्षा का विशेष महत्त्व

विधानपरिषद चुनाव : अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों और कैसे हारे अनंत सिंह?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का

नाम लंबे समय से मोकामा की सियासत और उनके व्यक्तिगत प्रभाव से जुड़ा रहा है। दूसरी ओर, नीरज कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दोनों के बीच पुरानी अदवावत ने चुनाव को ख़ास बना दिया।

सामान्य तौर पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होता है। यहां मतदाता पूरे विधानसभा क्षेत्र की आम जनता नहीं, बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत स्नातक मतदाता होते हैं। इसलिए किसी नेता की लोकप्रियता या विधानसभा चुनाव में उसकी सफलता अपने आप इस चुनाव में वोटों में तब्दील नहीं हो जाती।

यही इस मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी थी। अनंत सिंह के सामने सवाल था कि क्या मोकामा में उनका व्यक्तिगत प्रभाव पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक मतदाता समूह को प्रभावित कर सकता है ? वहीं नीरज कुमार के सामने अपनी सीट बचाने के साथ यह साबित करने की चुनौती थी कि पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद उनका राजनीतिक आधार कायम है।

निजी अदवावत ने बदला चुनाव का मुद्दा इस चुनाव की पृष्ठभूमि में नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच पुरानी राजनीतिक खींचतान थी। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरोध में कितना व्यापक होगा, यह निर्भर कर सकती है, तो यह साबित हो जाएगा कि उसकी ताकत वास्तविक है न कि केवल प्रशासनिक। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है, तो केंद्र यह प्रदर्शित करने में सफल हो जाएगा कि राज्य की सत्ता छिन जाने के बाद पी.टी.आई. की राजनीतिक पहुंच काफी सीमित हो जाती है। पी.टी.आई. ने यह प्रदर्शित किया है कि इमरान खान का जनाधार व्यापक बना हुआ है। फिर भी एक बड़ा वोट बैंक होने और उसे सड़क पर निरंतर लामबंदी में बदलने में सक्षम होने के बीच एक अंतर है।

अमीरात जैसे देशों के भारत के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंध हैं, जिनका महत्व उनके पाकिस्तान के साथ संबंधों से अलग है।

तीसरा पहलू रक्षा और सामरिक संतुलन का है। यदि भविष्य में इन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, उन्नत हथियारों की आपूर्ति या खुफिया सूचनाओं का व्यापक आदान-प्रदान बढ़ता है, तो भारत को पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीति की समीक्षा करनी पड़ सकती है। भारत को अपनी समुद्री निगरानी, रक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को लगातार मजबूत करना होगा।

चौथी चिंता ऊर्जा सुरक्षा की है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया के देशों से महत्वपूर्ण मात्रा में तेल और गैस प्राप्त करता है। यदि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़कर संघर्ष में बदलती है, तो तेल की कीमतों, समुद्री परिवहन और बीमा लागत पर दबाव पड़ सकता है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ सकता है।

इस बदलते समीकरण का दूसरा पक्ष भी है। सबसे पहला लाभ यह हो सकता है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को और गति दे। किसी भी संभावित चुनौती के मद्देनजर स्वदेशी हथियार निर्माण, आधुनिक निगरानी प्रणालियों, मिसाइल रक्षा और समुद्री सुरक्षा में निवेश बढ़ाना दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित में होगा। इससे भारत केवल किसी एक गंठबन्धन की प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि अपनी व्यापक सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप मजबूत बन सकेगा।

दूसरा अवसर कूटनीति का है। भारत



पिछले विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था। यह उनका आरोप था, जिसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

इस तरह मुकाबला तीन स्तरों पर पहुंच गया। पहला, नीरज कुमार की अपनी सीट बचाने की चुनौती। दूसरा, अनुज सिंह के लिए चुनाव जीतने का अवसर। तीसरा, अनंत सिंह के लिए अपनी राजनीतिक ताकत प्रदर्शित करने की परीक्षा।

अनंत सिंह के लिए यह केवल किसी दूसरे उम्मीदवार को जिताने का मामला नहीं रह गया था। उनके समर्थन का उद्देश्य नीरज कुमार को चुनौती देना भी था। लेकिन राजनीति में किसी विरोधी को हराने की इच्छा और अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने की क्षमता दो अलग-अलग बातें हैं।

यही अंतर इस चुनाव के विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। किसी नेता का किसी बचाने के साथ यह साबित करने की चुनौती थी कि पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद उनका राजनीतिक आधार कायम है।

निजी अदवावत ने बदला चुनाव का मुद्दा इस चुनाव की पृष्ठभूमि में नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच पुरानी राजनीतिक खींचतान थी। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरोध में कितना व्यापक होगा, यह निर्भर कर सकती है, तो यह साबित हो जाएगा कि उसकी ताकत वास्तविक है न कि केवल प्रशासनिक। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है, तो केंद्र यह प्रदर्शित करने में सफल हो जाएगा कि राज्य की सत्ता छिन जाने के बाद पी.टी.आई. की राजनीतिक पहुंच काफी सीमित हो जाती है। पी.टी.आई. ने यह प्रदर्शित किया है कि इमरान खान का जनाधार व्यापक बना हुआ है। फिर भी एक बड़ा वोट बैंक होने और उसे सड़क पर निरंतर लामबंदी में बदलने में सक्षम होने के बीच एक अंतर है।

है। यूरोप की परिषद ने 23 अक्टूबर 2026 के आसपास जारी अपने हालिया वक्तव्य में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और हिंसा करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करने तथा पुलिस बल के कानूनी और आनुपातिक इस्तेमाल पर जोर दिया है।

चार, भारत-यूरोप संबंधों में नई चर्चा: यदि यूरोपीय सरकारें भारतीय राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण, डिजिटल निगरानी के कानूनी ढाँचे या प्रशासनिक समन्वय जैसे क्षेत्रों में उपयोगी अनुभव पाती हैं, तो तकनीकी सहयोग और नीतिगत संवाद के अवसर बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ बताते हैं कि इसे अभी एक संभावित दिशा समझना चाहिए, न कि यूरोप द्वारा योगी मॉडल स्वीकार कर लेने का प्रमाण!

तीसरा अहम सवाल है कि क्या यूरोप में ‘बुलडोजर नीति’ भी अपनाई जा सकती है ? तो जवाब होगा कि यहीं पर इस बहस का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर ‘बुलडोजर मॉडल’ राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण हटाना और किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उसकी संपत्ति गिराना, दोनों अलग बातें हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 2024 को स्पष्ट किया कि केवल किसी आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, किसी की संपत्ति गिराना असंवैधानिक है। न्यायालय ने नोटिस, सुनवाई और न्यायिक समीक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए। लिहाजा, यूरोप में भी ऐसी किसी नीति को लागू करने के लिए स्थानीय कानून, संपत्ति अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई और आनुपातिक कार्रवाई के मानकों का पालन आवश्यक होगा। इसलिए यूरोप के

लिए संभावित सीख यह नहीं कि वह बिना कानूनी प्रक्रिया के कठोर दंडात्मक कार्रवाई अपनाए, बल्कि यह कि अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई प्रभावी, प्रमाण-आधारित और न्यायिक समीक्षा के अधीन हो।

चौथा महत्वपूर्ण सवाल है कि योगी मॉडल बनाम यूरोपीय व्यवस्था की तुलनात्मक दृष्टि क्या है ? इसे हमलोग विषय दर विषय, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश के मॉडल से जुड़ी बहस और यूरोपीय व्यवस्था की प्रमुख कसौटी के आधार पर निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं–

एक, अपराध नियंत्रण– पुलिस कार्रवाई और अपराधियों पर दबाव – प्रभावी जाँच, अभियोजन और निष्पक्ष सुनवाई।

दो, हिंसक भीड़– सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करना– हिंसक व्यक्तियों पर कार्रवाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सुरक्षा।

तीन, संपत्ति संबंधी कार्रवाई– अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना, कानून के अनुसार नोटिस, सुनवाई और अपील।

चार, पुलिस की जवाबदेही– प्रशासनिक अनुशासन और कार्रवाई– आनुपातिक बल प्रयोग, स्वतंत्र जाँच और जवाबदेही।

पांच, शासन की विश्वसनीयता– नागरिक सुरक्षा और कानून का प्रवर्तन– सुरक्षा के साथ मौलिक अधिकारों का संरक्षण।

यूरोप की परिषद के मानवाधिकार मानकों में पुलिस कार्रवाई के लिए आवश्यकता, आनुपातिकता और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। ये मानक हिंसक घटनाओं से निपटने के साथ-साथ शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को रक्षा भी करते हैं।

ख़ैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पी.टी.आई. के लिए परीक्षा

तिलक देवाशर

11 अक्तूबर को ख़ैबर पख्तूनख्वा (के.पी.के.) में आपातकाल और राज्यपाल शासन लागू किए जाने को इस्लामाबाद द्वारा मुख्य रूप से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद से निपटने में प्रांतीय सरकार को विफलता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि, इस आख्यान (नैरेटिव) के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा छिपा है जो इमरान खान की पाकिस्तान तरीक़-ए-ईसाफ़ (पी.टी.आई.), इस प्रांत और खुद संघीय सरकार का भविष्य तय करेगा। मुद्दा यह है कि क्या पी.टी.आई. प्रांत की सरकारी मशीनरी के बिना प्रभावी ढंग से लामबंद हो सकती है और टिकी रह सकती है, या फिर क्या केंद्र वास्तव में उस आतंकवाद पर काबू पा सकता है जब उसने के.पी.के. पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। संघीय सरकार ने सीधे सैन्य शासन के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता था, वह उठा लिया है। संविधान के अनुच्छेद 232 के तहत आपातकाल और अनुच्छेद 234 के तहत रान्यपाल शासन लागूया गया है। यह कदम इस्लामाबाद और के.पी.के. की पी.टी.आई. सरकार के बीच उनके जेल में बंद नेता इमरान खान की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए निकाले जाने वाले ‘लॉंग मार्च’ को लेकर हफ्तों चले टकराव के बाद उठाया गया है। इस्लामाबाद ने आतंकवादी हमलों में भारी वृद्धि और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से प्रांतीय सरकार के ‘जानबूझकर अलग हटने’ का हवाला देकर इस हस्तक्षेप को उचित ठहराया है। हालांकि, इसका समय बहुत कुछ बर्बा करता है। इस्लामाबाद की ओर पी.टी.आई. के ‘लॉंग मार्च’ की बढ़ती रफ्तार ने तात्कालिक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की। के.पी.के. 13 वर्षों से पी.टी.आई. का गढ़ रहा है। पार्टी के लिए इसका महत्व कभी केवल चुनावी नहीं रहा। सरकार

इस्लामिक नाटो की चुनौती : भारत के लिए कितना नुकसान ?

सौरभ वार्णय

दुनिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में नए सामरिक गठबंधनों का उभरना किसी एक देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ता है। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच रक्षा सहयोग तथा मुस्लिम देशों के बीच सामरिक समन्वय को लेकर हुई गतिविधियों ने भारत की विदेश नीति के सामने नए सवाल खड़े किए हैं। इन देशों के बीच उभरते रक्षा सहयोग को कुछ विश्लेषक इस्लामिक नाटो की संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि, इसे नाटो जैसा औपचारिक, एकीकृत सैन्य गठबंधन मानना अभी जल्दबाजी होगी। भारत के लिए असली प्रश्न यह है कि इस बदलते समीकरण से उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

नाटो एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है, जिसकी सदस्यता, संस्थागत व्यवस्था और सामूहिक रक्षा संबंधी स्पष्ट प्रतिबद्धताएँ हैं। इसके विपरीत, मुस्लिम बहुल देशों के बीच रक्षा समझौतों और सहयोग की पहल को उसी स्तर का गठबंधन मानने से पहले उसकी शर्तों, सैन्य प्रतिबद्धताओं और वास्तविक कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के हित कई मुद्दों पर समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएँ हर विषय पर एक जैसी नहीं हैं।

सऊदी अरब की प्राथमिकता अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और आर्थिक विकास की रक्षा करना है। पाकिस्तान



अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, जबकि तुर्किये क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने का इच्छुक है। इन देशों का आपसी सहयोग भविष्य में कितना व्यापक होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे साझा हितों को ठोस सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदल पाते हैं।

भारत के लिए पहली चिंता पाकिस्तान की भूमिका है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध लंबे समय से आतंकवाद, सीमा पर घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी विवादों से प्रभावित रहे हैं। यदि किसी नए रक्षा सहयोग के माध्यम से पाकिस्तान को अतिरिक्त सैन्य संसाधन, तकनीकी सहायता, खुफिया सहयोग या कूटनीतिक समर्थन मिलता है, तो इससे भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, केवल रक्षा समझौते के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सहयोगी देश पाकिस्तान के प्रत्येक कदम का समर्थन करेंगे।

दूसरी चिंता कश्मीर और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरुद्ध संभावित कूटनीतिक लामबंदी की है। यदि कुछ देश पाकिस्तान के पक्ष में साझा रुख अपनाते हैं, तो भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अधिक कूटनीतिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। लेकिन मुस्लिम देशों को एक ही राजनीतिक दृष्टिकोण वाला समूह मानना भी गलत होगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब

इजराइल आम चुनाव : नई सरकार का गठन अधर में लटका, आगयी अस्थिरता!

शोभना जैन

तीखे, कड़वाहट भरे चुनाव प्रचार के बाद इजराइल में हुए आम चुनाव की लगभग अंतिम दौर की मतगणना से पहले फिलहाल वहां नई सरकार का गठन अधर में लटका प्रतीत होता है। आशंका है कि यह स्थिति देश को राजनैतिक अस्थिरता की ओर न ले जाए। इजराइल में हमास के 7 अक्तूबर 2023 के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच इस सप्ताह हुए आम चुनाव में 77 प्रतिशत, दो दशकों में अब तक के सबसे भारी मतदान के बावजूद मतदाताओं का किसी एक गठबंधन के प्रति साफ जवाबदेह नहीं नजर आ रहा है। इस स्थिति के चलते दोनों पक्षों की तरफ से सरकार बनाने के लिए विचार विमर्श या यूँ कहें जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन आशंका है कि कहीं ऐसी सरकार से राजनैतिक अस्थिरता तो नहीं पनपेगी और फिर सरकार बनने की स्थिति में गठबंधन के तमाम घटकों को साथ रखने के लिए किए जाने वाले समझौते कितने स्थाई रहेंगे। इन चुनावों का एक अहम पहलू भी सामने आया है और वह यह है कि अरब नेतृत्व वाली पार्टियाँ चुनाव में अच्छी बहुत हासिल कर रही हैं। ये पार्टियां 19 सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं। अब ये पार्टियां सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका के रूप में उभर सकती हैं। लेकिन यहूदी पार्टियों में से एक को छोड़कर बाकी सभी ने उनके साथ काम न करने का निर्णय लिया है। इजराइल के आम चुनाव के आंशिक नतीजों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट से आए चल रहे हैं, हालांकि अभी वोटों की गणना का आखिरी दौर चल रहा है लेकिन दोनों ही पक्ष 120 सदस्यों वाली संसद में बहुमत का 61 जादुई आंकड़ा हासिल करने से अभी भी दूर हैं। इस संवेदनशील स्थिति के परिणामों को भांपते हुए राष्ट्रपति हर्जोग ने

चुनाव में 77 राजद की सरकार की साराहना की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि देश को नए चुनावों से बचना होगा। अगर अनिश्चय की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो सवाल पूछा जा रहा है कि इजराइल की अरब पार्टियां क्या अगली सरकार के गठन में अहम भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, अरब पार्टियों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी नेता उनकी भागीदारी या सरकार से बाहर रहते हुए समर्थन को स्वीकार करते हैं या नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के सहयोग पर आपत्तियां जताई गई थीं। यहां अहम बात यह है कि नेतन्याहू विरोधी दलों के पास संसद में बहुमत होने का मतलब अपने आप एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति होना नहीं है। नेतन्याहू का विरोध करने वाली पार्टियों के बीच इस बात पर मतभेद है कि वे अरब प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं या नहीं। अरब लोग उन लोगों के वंशज हैं, जो 1948 के अरब-इजराइल युद्ध के बाद इजराइल की ओर से घोषित सीमाओं के भीतर रह गए थे। इजराइल का गठन ब्रिटिश 'मैंडेट ऑफ फलस्तीन' से हुआ था, जहां उस समय करीब 12 लाख अरब मूल के लोग रहते थे। आज इजराइल की आबादी का करीब 21 प्रतिशत अरब मूल के हैं, यानी लगभग 20 लाख लोग। इनमें पूर्वी यरुशलम में रहने वाले कुछ लाख लोगों को छोड़कर सभी इजराइल के नागरिक हैं। पूर्वी यरुशलम के इन लोगों को कागजी समानता तो हासिल है लेकिन व्यवहार में उन्हें अन्य नागरिकों के तुलना में कम अधिकार हासिल हैं। अरब मूल के नागरिकों में बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं। हालांकि बड़ी संख्या में ईसाई और द्रुज़ समुदाय के लोग भी हैं। द्रुज़ समुदाय के लोग अपेक्षाकृत अधिक संख्या में अपनी पहचान इजराइल के रूप में स्वीकार करते हैं। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अरब पार्टियों की सरकार में भागीदारी तय नहीं है।

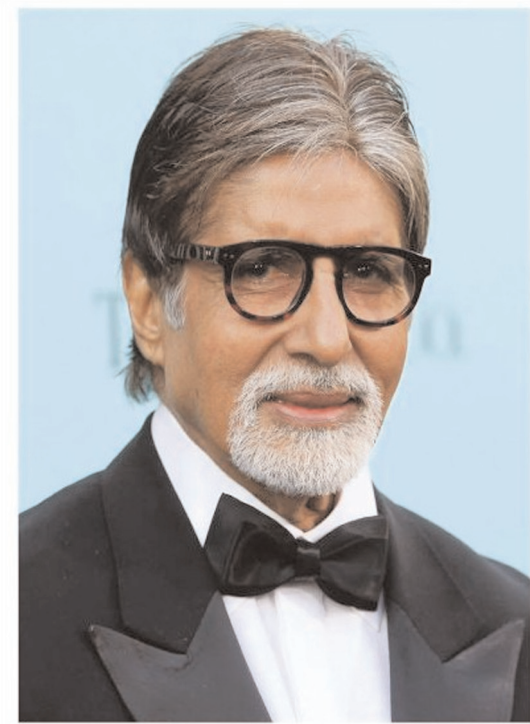
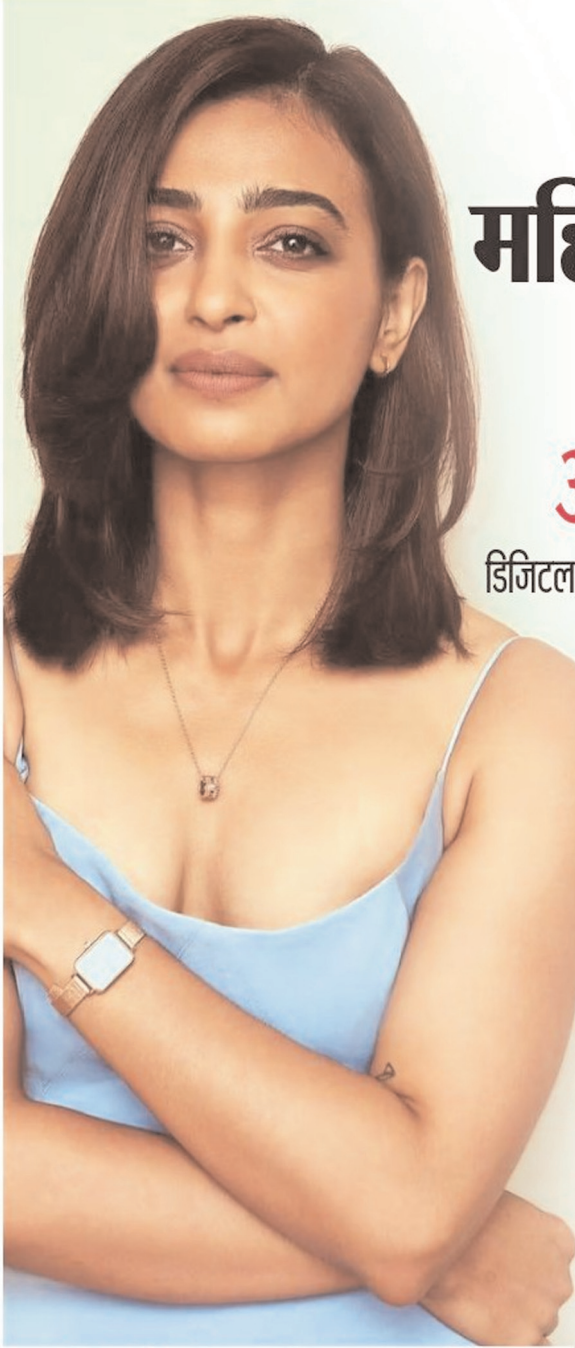


फिल्म ओम में दमदार पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगी अभिनेत्री साई पल्लवी

भारतीय सिनेमा के जाने-माने निर्देशक राजकुमार पेरियासामी की आगामी बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म ओम को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। इस फिल्म में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष और मलयालम सिनेमा के महानायक ममूटी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसी बीच निर्माताओं ने फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री साई पल्लवी के किरदार से पर्दा हटाकर प्रशंसकों के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। साई पल्लवी इस फिल्म में नित्या रेड्डी नाम की एक जांबाज और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाती हुई दिखाई देंगी। इस घोषणा के बाद से ही साई पल्लवी के नए और सख्त अवतार को देखने के लिए दर्शकों की बेताबी साफ नजर आ रही है। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी भी इस प्रोजेक्ट को और अधिक भव्य और प्रासंगिक बनाती है। फिल्म के शीर्षक के साथ चेंप्टर 1 जोड़ा गया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि यह एक बहुस्तरीय कहानी है और भविष्य में इसका सीकल भी दर्शकों के सामने आ सकता है। कुछ समय पहले जारी किए गए झलक वीडियो (टीजर) से यह साफ हुआ था कि फिल्म की मुख्य कहानी जंगलों में अवैध रूप से ताल चंदन की कटाई करने वाले मजदूरों और उनके संघर्षपूर्ण जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में धनुष एक लकड़हारे की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी में मुख्य मोड़ तब आता है जब पुलिस अधिकारी अवैध कटाई में शामिल मजदूरों को हथियार के बल पर बंदी बना लेते हैं और धनुष उनके रक्षक बनकर सामने आते हैं। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी मेकर्स ने काफी सूझबूझ से निर्णय लिया है। पहले इस फिल्म को अक्टूबर महीने में प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभिनेता धनुष ने सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया। इसके साथ ही, दिवाली के अवसर पर अन्य बड़ी फिल्मों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के व्यावसायिक टकराव से बचने के लिए निर्माताओं ने 20 नवंबर की तिथि को अंतिम रूप दिया है। धनुष और ममूटी जैसे दो विशाल अभिनेताओं का पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट में काम करना इस फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों की सूची में शामिल करता है।

लिटिल थॉमस को लेकर सुर्खियों में रसिका

अभिनेत्री रसिका दुग्गल इन दिनों अपनी नई फिल्म लिटिल थॉमस को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भले ही तकनीक के सहारे बड़े बजट और भव्य सेट वाली फिल्में बन रही हों, लेकिन आम जिंदगी से जुड़ी सीधी और सरल कहानियों की अपनी एक अलग अहमियत होती है। फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे थॉमस की बाल सुलभ जिज्ञासा और उसकी मासूमियत के इर्द-गिर्द घूमती है। वह जानना चाहता है कि बच्चे कहाँ से आते हैं और अपने लिए एक भाई या बहन की चाहत रखता है। रसिका दुग्गल के अनुसार, बच्चों के सवालों और उनकी उत्सुकता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दुनिया को बच्चों के नजरिए से देखना एक बेहद खूबसूरत अनुभव है। इस फिल्म में बचपन, पारिवारिक रिश्तों और वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव को सहज ढंग से दर्शाया गया है।



अभिनेत्री पवित्रा पुनिया ने एक महत्वपूर्ण संदेश किया साझा

विभिन्न लोकप्रिय धारावाहिकों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाली अभिनेत्री पवित्रा पुनिया ने देश में सामाजिक सौहार्द, शांति और धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने धर्म से सच्चा प्रेम करें, लेकिन साथ ही दूसरों के धार्मिक अकीदों और आस्थाओं का भी पूरा सम्मान करें। अपने बयान में अभिनेत्री ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि त्योहारों के व्यस्त सीजन के दौरान ऐसे प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जो एक विकासशील देश के लिए काफ़ी चिंताजनक है। पवित्रा पुनिया ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कई लोग बुनियादी तथ्यों को समझे बिना ऐसी आर्थिक समस्याओं और आंकड़ों का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने देश की जमीनी हकीकत पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जब कोई आम नागरिक दो वक्त की रोटी के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा हो, तब इस तरह के गतिरोध देश के हित में नहीं हो सकते। उन्होंने युवा पीढ़ी (जेन जी) का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ प्रभावकारियों (इन्फ्लुएंसर्स) द्वारा फैलाई जा रही मनगढ़ंत बातों और भ्रामक जानकारीयों से युवाओं को बचना चाहिए। युवाओं में अपार क्षमता और ज्ञान है, इसलिए उन्हें किसी के बहकावे में आकर अपनी सोच को दूषित नहीं करना चाहिए। एक सनातनी हिंदू होने पर गर्व व्यक्त करते हुए पवित्रा ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी भी अन्य समुदाय या धर्म के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने भारत के सामाजिक ताने-बाने को याद दिलाते हुए कहा कि बांटो और राज करो की विभाजनकारी सोच कुछ स्वार्थी तत्वों की देन है, जो देश की मूल भावना के विपरीत हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनके आसपास कई मुस्लिम परिवार रहते हैं और सभी लोग आपस में प्रेम, भाईचारे और शांति के साथ मिलकर रहते हैं। भारत की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता और एकता का अनूठा बंधन है, जिसे हर कीमत पर सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए।



फिल्म सेट पर महिलाओं के मतभेद की धारणा को राधिका आप्टे ने बताया गलत

डिजिटल क्रिएटर से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया

बॉलीवुड की बहुमुखी अभिनेत्री राधिका आप्टे जल्द ही आगामी डिजिटल वेब सीरीज अक्का में नजर आने वाली हैं। इस सीरीज में उनके साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री कीर्ति सुरेश भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में इस सीरीज के प्रचार के सिलसिले में बात करते हुए राधिका आप्टे ने फिल्म सेट पर महिला कलाकारों के आपसी संबंधों को लेकर वहाँ से चली आ रही रूढ़िवादी धारणाओं पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने उस प्रचलित सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें यह दावा किया जाता है कि जब दो महिला कलाकार किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम करती हैं, तो उनके बीच अवसर अनबन, मनमुटाव या झगड़े होते हैं। राधिका आप्टे का मानना है कि किसी भी कार्यस्थल का माहौल किसी व्यक्ति के लिंग से तय नहीं होता, बल्कि यह लोगों के आपसी तालमेल और व्यवहार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद पुरानी और आधारहीन सोच है कि महिलाएं आपस में तालमेल नहीं बैठा पातीं। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि कई बार पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक असुरक्षा की भावना देखी जाती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा पुरुष या महिला होने का नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत संबंधों और आपसी समझ का विषय है। किसी भी क्षेत्र में आप कुछ लोगों के साथ बहुत सहज महसूस करते हैं और आसानी

से घुल-मिल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ आपका मानसिक तालमेल नहीं बैठ पाता। वेब सीरीज अक्का के शूटिंग सेट का अनुभव साझा करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि वहाँ का माहौल अत्यंत सकारात्मक और उत्साहवर्धक था। सेट पर कैमरे के सामने काम करने वाली स्टारकास्ट और कैमरे के पीछे काम करने वाली तकनीकी टीम में महिलाओं और पुरुषों की लगभग समान भागीदारी थी। उन्होंने कहा कि सेट पर एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टरहुड यानी बहनौं जैसा माहौल था, जिसने पूरी शूटिंग प्रक्रिया को बहुत सहज और आनंददायक बना दिया। इसके साथ ही राधिका आप्टे ने यह भी रेखांकित किया कि काम के सिलसिले में किसी के साथ अच्छा तालमेल होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप उनके बहुत गहरे मित्र बन जाएं। बिना करीबी दोस्त बने भी एक पेशेवर और गरिमापूर्ण माहौल में बेहतरीन काम किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वेब सीरीज अक्का एक थ्रिलर गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें महिलाओं को मुख्यधारा में दिखाया गया है। इस सीरीज का निर्देशन धर्मराज शेठ्री ने किया है, जो इस शो के लेखक भी हैं। यह कहानी 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित एक काल्पनिक दुनिया को दर्शाती है, जिसे पीढ़ियों से महिलाओं ने ही बनाया, चलाया और संरक्षित रखा है। यह बहुप्रतीक्षित सीरीज 30 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है।

इंडो-रशियन फिल्म से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखेंगी सैयामी खेर, भाषा की सीमाओं से परे जा किया काम



फिल्म का निर्देशन रूसी निर्देशक मैक्सिम कुजनेत्सोव कर रहे हैं। सैयामी इससे पहले निर्देशक प्रियदर्शन की बहुचर्चित क्राइम थ्रिलर फिल्म हैवान में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और सेफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में थे।

अभिनेत्री सैयामी खेर जल्द ही एक इंडो-रशियन ड्रामा फिल्म के जरिए अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में अपना पदार्पण करने जा रही हैं। इस अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अपने अनुभवों को साझा करते हुए सैयामी ने बताया कि एक विदेशी कू के साथ मॉस्को में शूटिंग करना उनके लिए बेहद नया और रोमांचक अनुभव था। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने से कहानी को देखने और समझने का एक नया वैश्विक नजरिया मिलता है। सैयामी खेर के अनुसार भाषा और देश की सीमाओं से परे जाकर काम करना किसी भी कलाकार के लिए सीखने का बहुत बड़ा अवसर होता है। हालांकि उन्होंने फिल्म की विस्तृत कहानी का खुलासा नहीं किया, लेकिन बताया कि यह एक मजबूत महिला चरित्र पर आधारित गहन ड्रामा फिल्म होगी। इस



मां बनने के बाद शरीर में आए बदलावों और मानसिक संघर्ष पर करिश्मा तन्ना का छलका दर्द

हाल ही में मातृपद प्राप्त करने वाली मशहूर अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने प्रसव के बाद महिलाओं के शरीर में होने वाले प्राकृतिक बदलावों और उससे जुड़ी मानसिक चुनौतियों पर बेहद संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि एक नन्हें शिशु को जन्म देने के बाद अपने बदले हुए शरीर को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बिटाना कभी-कभी काफी कठिन और थकाऊ साबित होता है। अभिनेत्री ने अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार उन्हें गर्भावस्था से पहले वाले अपने सुगठित शरीर की बेहद याद आती है। जब भी वह आईने के सामने खड़ी होती हैं, तो पेट का ढीलापन, त्वचा में आई शिथिलता और शारीरिक आकार में आए बदलाव उन्हें स्पष्ट नजर आते हैं। कपड़े खरीदने या तैयार होने की इच्छा भी ऐसे समय में अवसर खत्म हो जाती है, जो किसी भी नई मां के लिए मानसिक रूप से काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि, करिश्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी स्थितियों में खुद के प्रति कटोर होने के बजाय दयालुता का भाव रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने खुद को यह याद दिलाया कि उनके शरीर ने एक नए जीवन को जन्म दिया है और उसके विकास के लिए नौ महीनों तक सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। शिशु के जन्म को अभी केवल ढाई महीने का समय ही बीता है, ऐसे में इतनी जल्दी पुरानी शारीरिक संरचना को वापस पाने की उम्मीद लगाना बेमानी है। करिश्मा का मानना है कि एक महिला एक ही समय में मां बनने के सुखद अनुभव के प्रति आभारी भी हो सकती है और साथ ही अपने पुराने स्वरूप को खोने का दर्द भी महसूस कर सकती है। यह दोनों भावनाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं और इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। अभिनेत्री ने जोर देकर कहा कि जिस कोमलता और प्रेम की हकदार माएं अपने बच्चों को मानती हैं, वही कोमलता उन्हें खुद अपने प्रति भी दिखानी चाहिए। वे अब अपनी शारीरिक बनावट की आलोचना करने के बजाय अपने शरीर को ठीक होने, मजबूत बनने और पुनः सहज महसूस करने का पूरा समय दे रही हैं। उन्होंने अन्य सभी माताओं को सात्वना देते हुए कहा कि वे इस मानसिक और शारीरिक सफर में बिल्कुल अकेली नहीं हैं। गौरतलब है कि करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा ने इस वर्ष अप्रैल में अपने पहले बच्चे के आगमन की खुशखबरी साझा की थी, जिसके बाद जुलाई में उनके घर एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ।

परिणीति के समर्थन में उतरीं जेनिफर

वेब सीरीज शकः ट्रस्ट नो वन की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित एक पार्टी के दौरान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वायरल वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे परिणीति ने अपनी सह-कलाकार जेनिफर विंगेट को फोटो विलक कराने के दौरान नजर अंदाज किया। अब इस विवाद पर खुद जेनिफर विंगेट ने चुप्पी तोड़ी है और परिणीति चोपड़ा का समर्थन करते हुए सभी तरह



की अफवाहों और ट्रोलिंग को खारिज कर दिया है। जेनिफर विंगेट ने स्पष्ट किया कि उनके और परिणीति के बीच किसी भी प्रकार की अनबन नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी के दौरान मंच पर जगह की कमी थी, जिसके कारण वे स्वयं पीछे हट गई थीं। परिणीति हमेशा उनके प्रति बहुत ही दयालु और सम्मानजनक रही हैं। जेनिफर ने लोगों से अपील की कि वे इस साधारण सी बात को गलत रूप देकर नकारात्मकता न फैलाएं।

अमिताभ बच्चन ने पारंपरिक अंधविश्वासों पर उठाए सवाल कहा- आधुनिक पीढ़ी मानती है केवल वैज्ञानिक तर्क

भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अवसर अपने विचारों और अनुभवों को अपने व्यक्तिगत ब्लॉग के माध्यम से प्रशंसकों के साथ साझा करते रहते हैं। अपने एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने समाज में गहराई से रची-बसी पुरानी परंपराओं, मान्यताओं और अंधविश्वासों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकांश लोग बिना किसी तर्क या अर्थ को समझे केवल पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही प्रथाओं का पालन करते आ रहे हैं। अपने इस लेखन में उन्होंने इस बात पर गहराई से प्रकाश डाला कि किस प्रकार समय बीतने के साथ इंसान की व्यक्तिगत इच्छाएं, सोच और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि इंसान के जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब वह उन सभी चीजों को दोबारा करना चाहता है, जिनसे उसे अतीत में रोका गया था। उन्होंने जीवन के बदलते चक्र का वर्णन करते हुए कहा कि एक समय में इंसान पूरी तरह से बेफिक्र होता है और फिर जीवन के उत्तरार्ध में वह दोबारा उसी बेफिक्री को पाना चाहता है। इंसान का दिमाग कई बार अजीब तरह से निर्णय लेता है, लेकिन यह प्रक्रिया इंसान को एक अलग प्रकार का मानसिक सुकून भी प्रदान करती है। परंपराओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने

शनिवार को नाखून न काटने जैसी मान्यताओं का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि शनिवार को नाखून न काटने को अशुभ माना जाता है और यह प्रथा केवल अज्ञात डर के कारण आज भी समाज में अपनी जगह बनाए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने रत्नों से जुड़े अंधविश्वासों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि लोग कहते हैं कि हरा पत्थर मत पहनो, बल्कि उसकी जगह एक हरे रंग की शॉल अपने पास रख लो। इस पर सवाल उठाते हुए अमिताभ बच्चन ने पूछा कि उस निर्दोष पत्थर ने किसी का क्या बिगाड़ा है और पास में रखी हरी शॉल किसी व्यक्ति के लिए किस प्रकार लाभदायक साबित हो

सकती है। इन खोखले तर्कों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि डर के कारण लोग आज्ञाकारी बनकर इन प्रथाओं को स्वीकार करते रहते हैं। हालांकि, महानायक ने यह भी स्वीकार किया कि आज की आधुनिक पीढ़ी अंधविश्वासों को आख मूंदकर स्वीकार नहीं करती है। वर्तमान पीढ़ी किसी भी प्रथा को अपनाने से पहले उसके पीछे के वैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक कारणों को समझती है। आज के युवा केवल उन्हीं परंपराओं और जीवनशैली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हो सके।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	प्रमुख समाचार
विपक्ष का जन महाभियोग कार्यक्रम टला	नईदिल्ली। सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग का कार्यक्रम, जो शुक्रवार को यहां आयोजित होने वाला था, शहर के मौसम को देखते हुए टाल दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अब यह सार्वजनिक महाभियोग 31 अक्तूबर को होने की संभावना है। यह तारीख विपक्षी गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली रैली से एक दिन पहले की है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ आयोजित की जा रही है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और तालकटोरा स्टेडियम जैसी अन्य जगहें नहीं मिल पाईं, जिसके बाद इस जगह (खरगे के आवास) को चुना गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अगले दिन, हम रामलीला मैदान तक एक मार्च निकालेंगे। इसमें पूरा विपक्ष और जो भी आना चाहे, वे सभी शामिल हो सकते हैं।

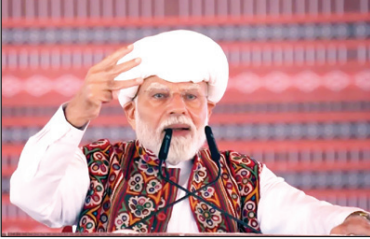
पीएम-किसान सम्मान निधि जारी कर विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी

कहा- संकट के समय में फैलाई जा रही अफवाहें

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे ईरान में चल रहे युद्ध के बीच देश में अफवाहें फैला रहे हैं और घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता एक राष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर उनकी सरकार को निशाना बना रहे हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला करते हुए मोदी ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो देश को मुसीबत में देखना चाहते हैं। जब भी देश पर कोई संकट आता है, तो ये लोग खुश होते हैं। ईरान में चल रहे संघर्ष का हालिया उदाहरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जहाँ एक ओर देश युद्ध से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट हो रहा था, वहीं दूसरी ओर विपक्ष गलत जानकारी फैलाने में लगा हुआ था।

मोदी ने शुक्रवार को पिछली सरकारों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में बिताए अपने वर्षों को याद करते हुए सभा में कहा कि मुझे आपकी सेवा करते हुए 25 साल हो गए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने



इस मूल्य वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। सरकार ने इस पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि खेती हमारी संस्कृति है। हमने खेती और पशुपालन को तकनीक से जोड़ा है। आज किसानों को 26 करोड़ से ज्यादा सॉलड हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) मिल चुके हैं। पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसमें हमारी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी है। पिछले एक दशक में, हमने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया है।

मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर को सार्वजनिक पद पर मेरे 25 साल पूरे हो गए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब मैंने अक्टूबर 2001 में पहली बार पद की शपथ ली थी; तब आपने मुझ पर बहुत प्यार बरसाया था। उन्होंने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त भी जारी की, जो 19,000 करोड़ रुपये की है। इस नई किस्त के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान – जिन्हें उन्होंने देश का अन्नदाता बताया – भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के सशक्तिकरण और कल्याण को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के किसानों के खातों में पीएम-किसान की एक और किस्त पहुँच गई है। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। हमारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आज यहां दो बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। हमारा लक्ष्य साफ है, पशु स्वस्थ हों, दूध उत्पादन बढ़े और गोबर का भी पूरा उपयोग हो। हम पशुपालन को केवल परंपरा नहीं, किसान की आमदनी बढ़ाने और गांव को समृद्ध बनाने का साधन बना रहे हैं।

गुजरात को मिलीं 14,000 करोड़ रुपये की योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बनासकांठा में एक रोडशो के साथ अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। यहाँ 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई या उन्हें आगे बढ़ाया गया। इन योजनाओं में कृषि, परिवहन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, डेयरी विकास और बाल कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं उत्तर गुजरात पर केंद्रित हैं। इसके बाद, 31 अक्टूबर को वे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे, जहां वे सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भारत पर्व 2026 का उद्घाटन, आकर्षक रोशनी वाली सजावट और 400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत शामिल होगी। बनावकाना में डेयरी विकास और कृषि मुख्य केंद्र हैं।

सेंसेक्स 308 अंक चढ़ा

निफ्टी 23,053.10 के पार

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार का समापन हरे निशान पर हुआ। शुरुआती कारोबार सेंसेक्स 308.49 अंक चढ़कर 74,459.53 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, 50 शेयरों का निफ्टी बेंचमार्क 116.35 अंक चढ़कर 23,053.10. के स्तर पर बंद हुआ। रुपया 33 पैसे की बढ़त के साथ 94.93 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इफ्टी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में तेजी दर्ज की गई। आईटी कंपनियों में मजबूत खरीदारी और टाटा समूह की खुदरा इकाई ट्रेट में आय-आधारित मांग ने बाजार को सहारा दिया। इस उछाल से निवेशकों में उत्साह देखा गया। सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेट के शेयरों में 5.20 फीसदी का उछाल आया। टाटा समूह की इस खुदरा इकाई ने गुरुवार को सितंबर तिमाही के लिए 468 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

ललित गर्ग

किसी राष्ट्र की प्रगति केवल ऊँची इमारतों, चमचमाती सड़कों और बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसकी उद्यमशीलता कितने लोगों के जीवन को बदलती है, तकनीक कितनी दूर तक पहुँचती है और आर्थिक शक्ति किस सीमा तक जनसामान्य की आकांक्षाओं को पंख देती है। भारत की विकास यात्रा में रिलायंस समूह और जियो की कहानी इसी व्यापक परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारत के औद्योगिक इतिहास में टाटा समूह ने विश्वास, संस्थागत मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और दीर्घकालीन दृष्टि की मजबूत विरासत निर्मित की है। दूसरी ओर, रिलायंस समूह ने बड़े पैमाने पर निवेश, बाजार की नब्ज पहचानने, तकनीक को जनसुलभ बनाने और नए क्षेत्रों में निर्णायक प्रवेश करने की क्षमता से अपनी

अलग पहचान बनाई है। दोनों समूह भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ऐसे में रिलायंस का टाटा समूह से आगे निकलना किसी एक की पराजय और दूसरे की विजय भर नहीं है, इसे भारतीय उद्योग जागत में प्रतिस्पर्धा के नए अध्याय के रूप में देखना अधिक उचित होगा। जियो की यात्रा एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश के बाद उसने इंटरनेट सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने, डेटा की कीमतों में व्यापक बदलाव लाने और डिजिटल गतिविधियों को आम नागरिक तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जियो की असली उपलब्धि केवल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी का दायरा विस्तृत करना है।

रिलायंस की सफलता को मुकेश अंबानी के नेतृत्व में विकसित दीर्घकालीन कारोबारी दृष्टि, बड़े निवेश और बदलते समय

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

आईडीबीआई बैंक विनिवेश पर

वित्त मंत्री का राहुल को जवाब

नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक में एनडीए सरकार द्वारा किए गए रणनीतिक विनिवेश का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने पिछली कांग्रेस के नेतृत्व

वाली सरकारों पर व्यवस्थित वित्तीय कुप्रबंधन, राजनीतिक पक्षपात और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गलत तरीके से कर्ज देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री की यह टिप्पणी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई उस तीखी आलोचना का सीधा जवाब थी, जिसमें उन्होंने आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी को बेचे जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। एक्स पर, सीतारमण ने भारतीय वित्तीय इतिहास के कई उदाहरण दिए—जिनमें 1957 का मुंद्रा घोटाला, 1976 में एसबीआई के चेयरमैन आर.के. तलवार को हटाना, और 1980 के दशक तथा यूपीए के कार्यकाल के दौरान कथित राजनीतिक दबाव शामिल हैं।

राहुल गांधी चुनाव आते ही करते हैं हिंदू होने का दिखावा : भाजपा

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने

हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी की पुरानी टिप्पणियों का एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता चुनाव नजदीक आने पर हिंदू होने का दिखावा करते हैं। यह घटनाक्रम गांधी द्वारा ‘त्रिपुंड तिलक’ की तस्वीर साझा करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। भगवान शिव से जुड़ा यह पवित्र चिह्न माथे पर लगाया जाता है। गांधी ने इस तस्वीर के साथ ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ लिखा था। उन्होंने यह तस्वीर सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत द्वारा 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी किए जाने के बाद साझा की थी।

भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सबसे पहले गांधी की ‘एक्स’ पोस्ट दिखाई गई और इसके बाद तुलना के लिए हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म पर उनके भाषणों के कुछ अंश शामिल किए गए। वीडियो के पृष्ठभूमि में ‘क्या हुआ तेरा वादा’ गाना बज रहा था। भाजपा ने ‘एक्स’ पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, “अगर आप हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं, तो हर बार चुनाव आने पर हिंदू होने का दिखावा क्यों करते हैं, राहुल जी?” वीडियो के एक अंश में गांधी को यह कहते सुना जा सकता है, “हमें इन हिंदुत्ववादियों को एक बार फिर बाहर निकालना होगा।”

एक अन्य अंश में राहुल कहते सुनाई देते हैं, “जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे दिन के 24 घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा में लगे रहते हैं। नफरत, नफरत, नफरत। झूठ, झूठ, झूठ।” भाजपा ने ‘एक्स’ पर एक अन्य पोस्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया की आलोचना करने की लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। पार्टी ने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए न तो कोई कानून था और न ही कोई समिति।

भाजपा ने कहा, “क्या आपको पता है ? कांग्रेस के शासनकाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए न तो कोई कानून था और न ही कोई समिति। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी मर्जी से नाम तय करते थे और विपक्ष के नेता से सलाह तक नहीं ली जाती थी।” भाजपा ने कहा, “आज वही कांग्रेस एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था पर सवाल उठा रही है।”

क्रेडिट कार्ड में 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। भारत में क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी और भुगतान करने की रफ्तार सितंबर 2026 में धीमी पड़ गई। देश में क्रेडिट कार्ड से होने वाला कुल खर्च सालाना आधार पर 5.9 फीसदी घटकर 2.04 लाख करोड़ रुपए रह गया। फरवरी 2021 के बाद यह पहली बार है, जब क्रेडिट कार्ड खर्च में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, खर्च में आई इस गिरावट का मतलब यह नहीं है कि लोगों ने खरीदारी करना बंद कर दिया है। इसके पीछे पिछले साल का मजबूत बेस, त्योहारी खरीदारी का अक्टूबर में शिफ्ट होना और ऑनलाइन शॉपिंग में आई सुस्ती जैसे कई कारण हैं। खास बात यह है कि क्रेडिट कार्ड से खर्च घटने के बावजूद देश में कार्डों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 में क्रेडिट कार्ड से कुल 2.04 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए।



के अनुरूप व्यवसाय का विस्तार करने की रणनीति के संदर्भ में समझना चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने जिस उद्यमशीलता को व्यापक जनभागीदारी और पूँजी बाजार से जोड़ने की नींव रखी, उसे आगे बढ़ाते हुए समूह ने पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, खुदरा व्यापार और दूरसंचार जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की। जियो ने इस विरासत को डिजिटल युग की आवश्यकताओं से जोड़ा। इस यात्रा का संदेश स्पष्ट है—समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है, जो समय की समझ पहचान लेता है, वही भविष्य की दिशा तय करने लगता है। 28 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्मस की शेयर बाजार में ऐतिहासिक सूचीबद्धता ने इस

कोर्ट ने लालू और तेजस्वी पर

आरोप तय करने टाली सुनवाई

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव,

उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन के आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया 19 नवंबर तक के लिए टाल दी। विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से स्थगन के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए सुनवाई 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को किसी उच्चतर अदालत के आदेश के तहत पेशी से छूट मिली हुई है और जिनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई गई है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहना होगा। ईडी ने इस मामले में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था। इससे पहले, 10 सितंबर को पिछली अदालत ने सात आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था।

शाह ने सपा को दिलाई रामभक्तों पर गोलीकांड की याद

अखिलेश बाबू, यूपी में भाजपा अंगद का पैर, कोई हिला नहीं सकता : गृहमंत्री

लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान अयोध्या में राम भक्तों पर हुई गोलीबारी का जिक्र किया और दावा किया कि राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में यूपी भाजपा की कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, शाह ने उन्हें भाजपा का मालिक बताया और सम्मानपूर्वक राम-राम कहकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और 2017 तथा 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को याद किया।

समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या गोलीकांड का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर गोलीबारी हुई थी, जिससे सरयू नदी रक्त-रंजित हो गई थी। अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि वे किस आधार पर प्रदेश में सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। शाह ने भाजपा की उपस्थिति को अटल बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की जड़ें अंगद के पैर की भांति अडिग हैं और आगामी चुनावों में भाजपा पुनः बहुमत हासिल करेगी। इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता की परवाह किए बिना अयोध्या में कारसेवा का मार्ग प्रशस्त किया था।

शाह ने कहा कि वह भाजपा

दुलारचंद मर्डर केस में

जेल जाएंगे अनंत सिंह!

नईदिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी और जेडीयू से निकाले गए विधायक अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। मोकामा के विधायक के लिए यह एक बड़ा झटका है। आदेश जारी

करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत भी रद्द कर दी। यह आदेश पटना हाई कोर्ट द्वारा अनंत सिंह को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। इस याचिका में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम.एम. सुदेश और जस्टिस पी.वी. की बेंच ने जांच एजेंसी को भी निर्देश दिया कि वह इस हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करे। बेंच ने पटना हाई कोर्ट के 19 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत अनंत सिंह को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ठीक से विचार न करके गलती की है। जमानत को चुनौती देने वाली याचिका दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने दायर की थी।



कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने आए हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी जीत का श्रेय इन्हीं कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा मैं आज आप पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए, शाह ने महाभारत के अर्जुन का उदाहरण दिया और उनसे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहने को कहा।

उन्होंने कहा मैं आज आपसे आग्रह करता हूँ: कमर कस लें और अर्जुन की तरह अपना पूरा ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर टिकाए रखें। हम एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे। शाह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का समय आ गया है। उन्होंने पार्टी नेताओं को यह भी याद दिलाया कि बीजेपी का हर नेता सबसे पहले एक पार्टी कार्यकर्ता है।

गौतम अडानी ने एक दिन में कमाए 5.25 अरब डॉलर

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को आई तेजी का फायदा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को भी मिला। ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में जोरदार बढ़त के चलते उनकी नेटवर्थ में एक ही दिन में 5.25 अरब डॉलर यानी करीब 50 हजार करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही गौतम अडानी की कुल संपत्ति बढ़कर 110 अरब डॉलर पहुंच गई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, गुरुवार को दुनिया के अरबपतियों में सबसे ज्यादा संपत्ति गौतम अडानी की बढ़ी। इस बढ़त के बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 18वें स्थान पर हैं। इस साल अब तक उनकी संपत्ति में 18.2 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। 12 अक्टूबर के बाद यह उनकी नेटवर्थ में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है।

जियो की छलांग और विकसित भारत की नई आर्थिक गाथा

यात्रा को नया आयाम दिया। लगभग 30,213 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के बाद कंपनी का बाजार पूँजीकरण 12.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया और कारोबार के पहले दिन यह देश की दूसरी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई। रिलायंस समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त शेयरार मूल्य भी टाटा समूह से आगे निकल गया। ये आँकड़े भारतीय पूँजी बाजार के बदलते स्वरूप और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि बाजार पूँजीकरण कंपनियों के मूल्यंकन का पैमाना है, आम नागरिक की समृद्धि का नहीं। शेयर बाजार में ऊँचाई तभी सार्थक है, जब उसका लाभ अर्थव्यवस्था की जड़ों तक पहुँचे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदत्त अनंत अंबानी का भावपूर्ण वक्तव्य चर्चाओं में हैं, उन्होंने इस व्यावसायिक उपलब्धि को पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी

अन्नदाता किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला : विष्णु देव साय

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके हित में अनेक दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों के



बैंक खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से आर्थिक संबल मिल रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24

लाख 59 हजार 707 किसानों के बैंक खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 24 किस्तों में 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई है, जिससे

सहायता वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इस योजना से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के संचालन में सहायता मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दूरदर्शी पहल की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समस्त किसान परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

रमन सिंह की एनएसजी सुरक्षा भी हटाई जाएगी क्या : दीपक बैज

सुरक्षा हटाने के बाद कोई अनहोनी होती है तो क्या सरकार उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगी?



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने बस्तर सहित प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को रिव्यू किया है। गृह मंत्री का दावा है कि नक्सली समाप्त हो गये हैं। अतः सुरक्षा की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को नक्सल प्रभावित राज्य का मुख्यमंत्री रहने के कारण एनएसजी सुरक्षा मिली है। वे ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते हैं। उनको मुख्यमंत्री पद से हटे भी

8 साल से अधिक हो रहे हैं। यदि सभी की सुरक्षा नक्सल समाप्त होने के कारण हटाई जा रही तो क्या रमन सिंह की भी एनएसजी सुरक्षा हटाई जायेगी? उनको भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के अनेक

नेताओं विशेषकर बस्तर के भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा सीआरपीएफ का विशेष सुरक्षा दी गयी है क्या उसको भी हटाने के लिए राज्य सरकार अनुशंसा करेगा? यदि सुरक्षा को लेकर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुरक्षा हटाने के पहले क्या सरकार ने इंटीलिजेंस इनपुट लिया है कि जिनको अब तक सुरक्षा नहीं मिली है उनको अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है? बस्तर के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हटाने के बाद कोई अनहोनी होती है तो क्या सरकार उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगी?

अब घर बैठे बुक करें रेल पार्सल

रायपुर/ बिलासपुर। भारतीय रेल पार्सल सेवा को और अधिक सरल, सुविधाजनक एवं ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल के तहत रेल पार्सल ऐप - घर से घर तक विकसित किया जा रहा है। यह ऐप मोबाइल (एंड्रॉइड एवं आईओएस) तथा वेबसाइट, दोनों माध्यमों पर उपलब्ध होगा। इस ऐप के सुचारु संचालन एवं देशभर में विस्तार के लिए प्रारम्भिक स्तर पर 8 बड़े शहरों पर लागू किया जाएगा।

इस ऐप के माध्यम से ग्राहकों को अपना पार्सल लेकर स्वयं रेलवे पार्सल कार्यालय आने और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैलाडिला बुल्स ने 6-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की

रायपुर।बैलाडिला बुल्स के लिए अपने आखिरी लीग मैच में इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आज की जीत ही उसे सेमीफाइनल में पहुंचा सकती थी। टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चक्रधर चैंपियंस को 6-2 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

इस परिणाम के साथ ही संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने भी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। अब टॉप क्वालीफायर के रूप में न्यायधानी नाइट्स 31 अक्टूबर को शाम 5.30 बजे संस्कारधानी का सामना करेगी, जबकि इसके बाद शाम 7.30 बजे बैलाडिला और मैनपाट के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा।

मैच शुरू होने से पहले



चिंगोलेनसाना सिंह की टीम के सामने करो या मरो जैसी स्थिति थी, और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आनंद ने पहले ही मिनट में गोल करके अपनी टीम के इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शुरुआती हमले में एक %रिवर्स फिलक% लगाई, जो सीधे नेट में जाकर लगी। बुल्स ने गोल करने के लिए जबर्दस्त जज्बा दिखाया, खासकर पहले मैच में मिली हार के बाद। पहले क्वार्टर का सबसे अहम पल वह था जब उलेश्वर यादव ने

युवराज वाल्मीकि के खिलाफ एक %पेनल्टी स्ट्रोक% को बचा लिया, जिसने चैंपियंस को गोल करने से रोक दिया।

वहीं बुल्स ने अपने मिले मौके को गोल में बदल दिया। जसकर सिंह ने लीग में अपना 7वां गोल किया और टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना तीसरा गोल दागा।

इस अहम मुकाबले में जसकरण यहीं नहीं रुके। उन्होंने

तीसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना चौथा गोल किया। आनंद भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने चैंपियंस के कुछ डिफेंडरों को छकाते हुए एक और गोल कर दिया। इसके तुरंत बाद गोपाल ने पेनल्टी कॉर्नर रिबाउंड पर गोल किया, जिससे उनका गोल अंतर +2 हो गया और सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई।

चक्रधर के लिए यह बहुत निराशाजनक रहा। हालांकि एस.वी. सुनील ने अपनी टीम के लिए मौके बनाए, लेकिन फॉरवर्ड लाइन के बीच तालमेल की कमी दिखी। कप्तान ने संकल के अंदर कुछ बेहतरीन पास दिए, लेकिन गेंद को गोल में मोड़ने (फिनिश करके) के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह दूसरे क्वार्टर में खगेश्वर बाग ने एक गोल कर दिया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक प्रतीक्षा से राहत मिले और कम समय में अधिक किसान अपनी उपज का विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही प्रदेश में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति का उद्देश्य केवल केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों के लिए धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सुविधाजनक बनाना है।



शिक्षा विभाग में तबादला उद्योग चल रहा है : कांग्रेस

रायपुर। शिक्षा विभाग में हो रहे स्थानांतरण को कांग्रेस ने तबादला उद्योग बताया है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि शिक्षण सत्र के बीच में हो रहे तबादले कि शिक्षा विभाग में तबादले वसूली के लिये किये जा रहे हैं। पहले जिन शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण में तबादले किये गये उनको फिर शहरों में लाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री अपने विभाग की तबादला नीति सार्वजनिक करें। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का ढोंग रच रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा विभाग एक वसूली गिरोह की तरह काम कर रहा है। युक्तियुक्तकरण में नाम पर पूर्व में स्थानांतरित शिक्षकों में से अनेकों का पुनः तबादला प्राइम लोकेशन पर स्थित स्कूलों में कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि विगत 2 वर्षों में हुए शिक्षकों और प्राचार्य के 16,165 ट्रांसफरों में से मात्र 3,512 अर्थात 21.7 प्रतिशत ही एकल शिक्षकीय स्कूलों में भेजे गए। बाकी 78.3 प्रतिशत अर्थात 12,653 पदस्थापनाएं पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय बोली लगाकर बेची गईं। भाजपा की सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के नाम पर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।



संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या करने वाले सभी 22 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी समेत सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इममें उत्तर प्रदेश के कथित शूटर भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया। अब अदालत के फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को सकरी बाइपास पर संजू त्रिपाठी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में उत्तर प्रदेश से बुलाए गए शूटरों के शामिल होने का आरोप था। पुलिस ने कारोबारी के छोटे भाई कपिल त्रिपाठी को हत्या की साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया था। संजू और कपिल दोनों का अपराधिक गतिविधियों से जुड़ा इतिहास रहा है। पुलिस जांच के मुताबिक दोनों भाई शहर में विवादित जमीनों के सीढ़ों में दखल रखते थे और इससे लाखों रुपये कमाते थे।

ग्रामीण बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह होगी आसान

रायपुर। राज्य के ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा का विस्तार करने और विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के विशेष प्रयासों से धमरगिरी जिले के मगरलोड विकासखंड अंतर्गत ग्राम करेलीबड़ी तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2026 - 27 में दोनों महाविद्यालयों के लिए कुल 66 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर मिलेंगे। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार उच्च शिक्षा को गांवों और दूरस्थ अंचलों तक सुलभ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है।



सेवा सेतु से 3 दिनों में बना जाति निवास और आय प्रमाण पत्र

रायपुर। आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, सुगम एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा सेवा सेतु के माध्यम से आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। अब नागरिकों को डिजिटल सेवा व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से आवश्यक शासकीय दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल रही है। इसी क्रम में मुंगेली जिले के ग्राम खालबोरवा निवासी मोहन कोसले को महज 03 दिन के भीतर जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। श्री कोसले ने अपने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय स्थित सेवा सेतु केंद्र में जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई और मात्र तीन दिनों में उनके तीनों प्रमाण पत्र तैयार कर प्रदान कर दिए गए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली ने आवेदक श्री कोसले को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सौंपे



कलेक्टर, सीईओ सहित अधिकारियों ने मल्टीलेवल पार्किंग की छत से किया वायुसेना के जांबाज पायलटों का अभिवादन

भारतीय वायुसेना के ‘सारंग’ का गर्जन, रोमांचित हुए रायपुरवासी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आज राजधानी रायपुर का आसमान भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और अद्भुत उड़ान कौशल का साक्षी बना। भारतीय वायुसेना की विश्वप्रसिद्ध ‘सारंग’ हेलीकॉप्टर डिस्टले टीम ने राजधानी के आसमान में शानदार उड़ान भरकर रायपुरवासियों को रोमांचित कर दिया। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनते ही शहरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों और विभिन्न भवनों की छतों से इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया।

कलेक्टोरेट परिसर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग की छत पर

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन, एसडीएम नभ सिंह कोसले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने आसमान में उड़ान भरते सारंग हेलीकॉप्टरों को देखकर उत्साहपूर्वक हाथ हिलाकर भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों का अभिवादन किया।

राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में भी सारंग हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर नागरिकों में खासा उत्साह रहा। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिए, लोगों की



निगाहें उनकी ओर टिक गईं। घरों और कार्यालयों की छतों पर खड़े नागरिकों ने हाथ हिलाकर पायलटों का स्वागत किया। स्कूली बच्चों और युवाओं में विशेष रोमांच देखने को मिला। अनेक लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। भारतीय वायुसेना की इस शानदार उड़ान ने

पूरे शहर में देशभक्ति और गौरव का वातावरण निर्मित कर दिया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्टले टीम का राजधानी के आसमान में उड़ान भरना रायपुरवासियों के लिए गौरव और उत्साह का क्षण है। भारतीय

वायुसेना के जांबाज पायलटों का साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट उड़ान कौशल देश की सामरिक क्षमता एवं तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं तथा उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आगामी 2 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित संध लेक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्टले टीम द्वारा भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा।

रायपुर। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली ऐतिहासिक वोट बचाओ देश बचाओ रैली में छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता खाना होना शुरू हो गये है। प्रदेश भर से 25 बसो तथा ट्रेनों और हवाई जहाज से रवाना हुए। राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी सचिव विजय जांगिड़, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने बीटीआई मैदान में झंडी दिखाकर 15 बसों में कार्यकर्ताओं को रवाना किया। इसके अलावा कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बालोद, राजनांदगांव में भी अलग-अलग बसों से



कार्यकर्ता रवाना हुए। प्रदेश से कुल 25 बसे दिल्ली रैली में शामिल होने गई है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यह देश की जनता का ज्ञानेश कुमार और मोदी-शाह की तानाशाही के खिलाफ सीधा महाभियोग है। सत्ता के चमंड में चूर इन शासकों को यह

भूतना नहीं चाहिए कि जनता अब कमर कस चुकी है। वोट चोरी और लोकतंत्र का गला घोटने वालों का भूत 1 नवंबर को रामलीला मैदान से उतरा हुआ नजर आएगा। यह आंदोलन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के संविधान, मतदान के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई है।